



ONGC News as on 22 July 2026 (Print & Online)

Headline: Opportunities are booming here

इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और आइओटी से जुड़े कामकाज बढ़ने से पीएसयूज समेत आटोमेशन इंडस्ट्रीज में इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरों की मांग लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में ऐसे पेशवरों के लिए स्कॉप और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। आप भी कैसे इस उभरते क्षेत्र में एक चमकदार करियर बना सकते हैं, जानें एक्सपर्ट से...

दुनिया भर में तमाम उद्योग तेजी से आटोमेशन (स्वचालित प्रणाली) की ओर बढ़ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत सरकार 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग', 'ग्रीन एनर्जी', 'मिशन' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी योजनाओं के जरिये इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगभग सभी परियोजनाओं में आधुनिक आटोमेशन एवं प्रक्रिया नियंत्रण प्रणालियों का व्यापक उपयोग हो रहा है। इससे इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।

कड़ रहा स्कोप: आने वाले समय में इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ब्रांच का इतना स्कोप है कि हर सिस्टम में इसकी जरूरत होगी। पहले यह हाईवेयर ब्रांच ही माना जाता था, लेकिन साफ्टवेयर के क्षेत्र में जब से क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और आइओटी में इसका उपयोग होने लगा है, इस क्षेत्र में जाब के अवसर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूं समझें कि आने वाले समय में जितना भी एआई से जुड़ा कामकाज होगा, वहां इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए युवा केवल इंजीनियरिंग के चार-पांच कोर ब्रांचों जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल या कंप्यूटर साइंस के ही पीछे न भागें। यह देखें कि निजी और पब्लिक सेक्टर में वास्तविक स्कोप किस ब्रांच में है? जाब गारंटी वाले ब्रांच कौन से हैं? इस आधार



फोटो: मैग्नीफिक

प्रमुख संस्थान

- एनआईटी, जालंधर
www.nitj.ac.in
- नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी
आफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली
www.nsut.ac.in
- दिल्ली टेक्नोलॉजिकल
यूनिवर्सिटी (डीटीयू), दिल्ली
<https://dtu.ac.in>

आकर्षक पैकेज

इस क्षेत्र में वैतन पीएसयू के आकार पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय महत्व के पीएसयूज में डिप्लोमाधारकों को शुरुआत में न्यूनतम 40 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिल रहा है। कुछ पीएसयूज रुहे की सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। बीटेकधारकों को इन पीएसयूज में शुरुआत में करीब 12 लाख रुपये तक का सालाना पैकेज आफर हो रहा है। इस क्षेत्र में आपके लिए एटरोन्योरशिप के भी चांसेज हैं, जहां आप इस इंजीनियरिंग से जुड़ी सेवाएं/प्रोग्रामिंग सेवाएं देकर हर महीने लाखों रुपये कमा सकते हैं।

करने के बाद इस तरह के संस्थानों में आपको शुरुआत में जूनियर इंजीनियर की जाब मिल सकती है। यह एंट्री लेवल पद है। इसी तरह इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में ब्रीटेक करने वालों के लिए पीएसयू या आटोमेटेड इंडस्ट्री में ऑसिस्टेंट इंजीनियर की जाब आसानी से मिल सकती है। इसके बाद तबकी करके हुए वहां आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर जैसे पद तक पहुंच सकते हैं।

कोर्स एवं योग्यता: इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के इस क्षेत्र में दो तरह से आप करियर बना सकते हैं। 10वीं के बाद किसी पालीटेक्निक से इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर 12वीं के बाद एनडीए द्वारा आयोजित जेईई मेन परीक्षा क्लियर करके इंजीनियरिंग संस्थानों के इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग शाखा में प्रवेश पा सकते हैं। उपरोक्त डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश आमतौर पर अंक प्रतिशत के आधार पर होता है। यह डिप्लोमा करने के बाद आप चाहें तो इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का ब्रीटेक कोर्स भी कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद इस कोर्स में आपको लैटरल एंट्री के तहत ब्रीटेक के सेकंड ईयर में प्रवेश मिलेगा। हालांकि इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का यह ब्रीटेक कोर्स देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों में ही अभी संचालित हो रहे हैं।

(पीरेंड पाठ्य से वातवीत पर आधारित)

तेजी से बढ़ रहे यहां अवसर

पर इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग आपके लिए एक बेहतर करियर विकल्प हो सकता है। इसकी वास्तविकता जानने के लिए पिछले पांच सालों में पीएसयूज की वैकेंसीज का रिकार्ड देख सकते हैं। इस वैकेंसी रिकार्ड में इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की सबसे अधिक वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। विशेषज्ञों की मानें तो आने वाले दशक में जैसे-जैसे एआई, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट आफ थिंग्स (आइआओटी), स्मार्ट फैक्ट्रीज तथा डिजिटल प्रोसेस कंट्रोल का विस्तार होगा, इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग की मांग और अधिक तेजी से बढ़ेगी।

इसलिए कड़ रही है मांग: इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक मिला-जुला रूप है, लेकिन कंप्यूटिकेशन इसका हिस्सा नहीं है। आजकल आटोमेशन से जुड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी में इस ब्रांच का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह

आजकल यह इंजीनियरिंग की लीडिंग ब्रांच में से एक है।

इन क्षेत्रों में कड़ रहे रोजगार अवसर: डीआरडीओ, इसरो, एटामिक सेंटर, डीएमआरसी जैसे संस्थानों में पिछले पांच सालों में तमाम अन्य पदों के साथ इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग के पदों के लिए भी तमाम भर्तियां हुई हैं। अगर अन्य सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयूज) की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में रेलवे भर्ती बोर्ड, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, (ओएनजीसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल), गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल), हिंदुस्तान डर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर

कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से संबंधित बड़ी संख्या में रिक्तियां प्रकाशित की गई हैं, जो यह दर्शाती है कि आने वाले वर्षों में भी इस शाखा की मांग निरंतर बढ़ती रहेगी।

इसके अलावा, निजी क्षेत्रों में भी ऐसे इंजीनियरों की बहुत मांग देखी जा रही है, जैसे कि सीमेंट उद्योग, फार्मा उद्योग, आयल एवं गैस उद्योग, रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग, थर्मल एवं न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टील एवं धातु उद्योग, डर्वरक एवं रसायन उद्योग, जल शोधन संयंत्र, रेलवे एवं मेट्रो रेल, रक्षा एवं एयरोस्पेस, आटोमोबाइल उद्योग, सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग एवं इंडस्ट्री 4.0 आदि। दरअसल, इन सभी क्षेत्रों में प्रक्रिया नियंत्रण (प्रोसेस कंट्रोल), आटोमेशन तथा सुरक्षा प्रणालियों का संचालन इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरों द्वारा ही किया जाता है। डिप्लोमा

Publication : Mint

Editions : New Delhi

Date :22 July 2026

Page : 2



India's halt highlights the sharp pullback in shipping traffic through Hormuz. REUTERS

Refiners halt Iraq oil loadings as Hormuz risks rise

Bloomberg
feedback@livemint.com

Two Indian state-run refiners have suspended crude oil loadings from Iraq as mounting security risks in the Strait of Hormuz make it increasingly difficult to ensure safety of vessels, according to people familiar with the matter.

Indian Oil Corp. abandoned plans to load the supertanker *Lila Janmagar*, which can hold as much as 2 million barrels of oil, the people said, asking not to be identified because the matter is private. The refiner concluded it was too risky for a fully laden tanker to attempt a Hormuz crossing, after several freighters were struck by projectiles in recent days.

Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd., controlled by state-owned Oil and Natural Gas Corp., has also suspended lifting from Iraq because of the deteriorating security situation, the people said. Indian Oil, Mangalore Refinery and India's oil ministry didn't immediately respond to requests for comment.

India's halt further highlights the sharp pullback in shipping traffic through the Strait of Hormuz after Iran targeted multiple oil tankers in an attempt to assert control over the waterway. Vessels that had their transponders off to avoid detection have also come under fire, leaving shipowners with the big question about whether they're still willing to transit dark.

Indian state refiners typically purchase Iraqi crude under long-term contracts that requires the buyer to arrange shipping. The surge in maritime risks has also made securing tankers more difficult and expensive. Reuters first reported India's loading suspensions.

The country's shipping ministry has directed shipowners, managers and recruitment agencies to refrain from deploying Indian seafarers on vessels transiting Hormuz until further notice following the rise in attacks on commercial vessels.

Publication : Mumbai Samachar (Gujarati)	Editions : Ahmedabad
Date : 22 July 2026	Page : 11

Headline: Benchmarks fall 238 points as selling pressure increases, led by HDFC Bank

એચડીએફસી બેન્કની આગેવાનીમાં વેચવાલીનું દબાણ વધતા બેન્ચમાર્કમાં ૨૩૮ પોઇન્ટનું ગાબડું

(વાણિજ્ય પ્રતિનિધિ તરફથી)
મુંબઈ: એચડીએફસી બેંક, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ફોસિસ, ટાટા કન્સલ્ટન્ટ્સ સર્વિસીસ, પાવર ગ્રીડ અને આઇટીસી જેવા ઇન્ડેક્સ હેવીવેઇટ્સ શેરોમાં વેચવાલીના દબાણને કારણે વૈશ્વિક બજારોમાં સકારાત્મક વલણને અવગણીને, મંગળવારે ભારતીય ઇક્વિટી બેન્ચમાર્ક સતત બીજા સત્રમાં ઘટ્યા હતા.

સેન્સેક્સ ૨૩૮ પોઇન્ટ ઘટીને ૭૭,૪૭૦ પર બંધ થયો હતો અને નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ ૫૧ પોઇન્ટ ઘટીને ૨૪,૧૮૮ પર બંધ થયો હતો.

મધ્ય પૂર્વમાં મધ્યસ્થી પ્રયાસોએ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવને એક મહિનાની ટોચથી દૂર ધેલી દીધા હોવાથી એશિયન બજારો ઊંચા સ્તરે બંધ થયા હતા, જ્યારે રોકાણકારો કોર્પોરેટ પરિણામો પર નજર સાથે શેરલક્ષી કામકાજમાં ઓઠવાયા હતા. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ૧.૪૮ ટકા, સ્ટેટ બેન્કમાં ૧.૪૮ ટકા, ટીસીએસમાં ૧.૩૨ ટકા, ઇન્ફોસિસમાં ૧.૨૪ ટકા

અને ટ્રેન્ટમાં ૧.૧ ટકાનો કડકો જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે બજાજ ફિનસર્વ, ઇન્ટરગ્લોબ, અલ્ટ્રાટેક, એચસીલ, મહિન્દ્રા અને ટાઇટનમાં સુધારો જોવા મળ્યો હતો.

એસબીઆઇ ઈન્ડેક્સ શેર તેના ઇશ્યુ ભાવ સામે ૬.૨૭ ટકાના પ્રીમિયમ રૂ. ૬૧૦ના ભાવે લિસ્ટેડ થયા, તેનું માર્કેટ વેલ્યુએશન રૂ. ૧.૨૫ લાખ કરોડે પહોંચ્યું. માર્કેટ રેગ્યુલેટર ધી સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા પાસે કન્ઝ્યુમર એક્સપિરિઅન્સ સોલ્યુશન પ્રોવાઇડર કંપની ફ્યુઝન સીએક્સે અંદાજે રૂ. ૧૦૦૦ કરોડનો આઇપીઓ લાવવા માટે દસ્તાવેજ જમા કરાવ્યા છે. કંપની ૧૩ દેશમાં હાજરી ધરીવે છે અને આગામી સમયમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને જર્મની સહિતની નવી બજારોમાં પ્રવેશ ઉપરાંત એફિવિઝિશનની યોજના પણ ધરાવે છે. અત્યાર સુધીમાં કંપનીએ ૧૫ એફિવિઝિશન કર્યા છે.

પેટીએમે પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ૨૮ ટકાના વધારા સાથે રૂ. ૨૪૪૮ કરોડની રેવન્યુ

નોંધાવી, એબિટા રૂ. ૨૦૩ કરોડ રહ્યો. એડવિટ જવેલ્સ લિમિટેડે વાર્ષિક ધોરણે ૩૪ ટકા વૃદ્ધિ સાથે રૂ. ૧૬,૭૦૩ લાખની કુલ આવક, ૩૩ ટકાના વધારા સાથે રૂ. ૪,૮૨૪ લાખનો એબિટા તથા ૩૬ ટકાના વધારા સાથે રૂ. ૩૪૩૮ લાખનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો છે. એબિટા માર્જિન ૨૮.૪૮ ટકા અને ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન ૨૦.૫૮ ટકા રહ્યું છે. ગ્લેનમાર્કને નસલ સ્પ્રેના વિસ્તારિત વપરાશ માટે યુએસએફડીએની મંજૂરી મળી છે.

ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ પાસેથી તેજા એન્જિનિયરિંગે કુલ રૂ. ૧૮૧.૮૨ મિલિયનના ઓર્ડર મેળવ્યા છે. કંપનીએ મંડપેટા અને તાતીપાકા ઇન્સ્ટોલેશન્સ, રાજમુન્દ્રી એસેટ ખાતે ગેસ કમ્પ્રેશન સુવિધાઓ માટે ગવર્નમેન્ટ ઇ-મર્કેટપ્લેસ દ્વારા રૂ. ૧૫૩.૭ મિલિયન મૂલ્યનો ત્રણ વર્ષનો ઘમ કરાર મેળવ્યો છે. આ કરાર ૩ વર્ષ માટે અમલમાં મુકવામાં આવશે. યોગીજી ટીજીએ સેબી પાસે ડીઆરએચપી જમા

કરાવ્યું છે. રાલીસ ઇન્ડિયાનો પ્રથમ ક્વાર્ટરનો નફો ૩૧ ટકા વધીને રૂ. ૧૨૫ કરોડ થયો છે. અરવિંદ ફેશન્સે પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ૧૧ ટકાના વધારા સાથે રૂ. ૨૭.૬૧ કરોડનો નફો નોંધાવ્યો છે.

એશિયાઇ બજારોમાં જાપાનનો નિકકી ૩.૨૮ ટકા વધ્યો, ચીનનો શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ ૧.૭૮ ટકા વધ્યો અને દક્ષિણ કોરિયાનો કોસેપી ૩.૫૬% વધ્યો હતો. સ્થાનિક ધોરણે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા સંકલિત ૧૫ મુખ્ય સેક્ટર ગેજમાંથી આઠ નિફ્ટી પીએસયુ બેંક ઇન્ડેક્સના ૦.૮૮ ટકાના ઘટાડાને કારણે નીચા સ્તરે બંધ થયા. નિફ્ટી બેંક, ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ, એફએમસીજી, આઇટી, કન્ઝ્યુમર ગ્યુરેબલ્સ અને ઓઇલ એન્ડ ગેસ ઇન્ડેક્સ પણ ૦.૧૫ ટકા અને ૦.૬ ટકા જેવા ઘટ્યા હતા. બીજી બાજુ, ઓટો, મેટલ, ફાર્મા, રિયલ્ટી અને હેલ્થકેર શેરમાં ખરીદીનો રસ જોવા મળ્યો હતો.

નિફ્ટી મિડકેપ ૧૦૦ ઇન્ડેક્સ ૦.૩ ટકા વધ્યો અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ ૧૦૦ ઇન્ડેક્સ ૦.૫૩ ટકા વધ્યો, જેના કારણે

વ્યાપક બજારોએ તેમના મોટા સાથીદારો કરતાં વધુ પ્રદર્શન કર્યું. વ્યક્તિગત શેરોમાં, ટીવીએસ મોટરના શેર ૫.૬ ટકા વધીને રૂ. ૩,૭૮૨ પર બંધ થયો. કઝર વૈશ્ય બેંકના શેર ૧૩.૪૩% વધીને રૂ. ૩૪૧.૮૦ની ઇન્ટોડે ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યા, એચડીએફસી બેંક નિફ્ટી ઇન્ડેક્સમાં સૌથી વધુ નુકસાન કરનારી હતી, શેર બે ટકા ઘટીને રૂ. ૭૬૧ થયો. ઇન્ફોસિસ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ટાટા કન્સલ્ટન્ટ્સ સર્વિસીસ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ડી. રેડીઝ લેબ્સ, ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ, ટ્રેન્ટ, બજાજ ઓટો અને વિપ્રો પણ ૦.૮ ટકા અને ૧.૫ ટકાની વચ્ચે ઘટ્યા હતા.

બીજી બાજુ, નિફ્ટી ઇન્ડેક્સમાં શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફિનસર્વ, આઇશર મોટર્સ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, એચસીએલ ટેકનોલોજીસ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, ઇન્ડિગો અને કોટક મહિન્દ્રા બેંક ટોચના ઉછાળામાં હતા. એનએસઇ પર ૧.૮૧૨ શેર વધ્યા હતા જ્યારે ૧,૫૦૫ શેર નીચા ભાવે બંધ થયા હતા.

Bengal grants ONGC exploration & mining leases in 4 dists, boosts hydrocarbon hopes

Krishnendu.Bandyopadhyay
@timesofindia.com

Kolkata: In a significant step towards emerging as a hydrocarbon-producing state, the Bengal govt has recently granted petroleum exploration and mining leases to the Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) in Murshidabad, Nadia, North 24 Parganas and East Burdwan districts.

Presenting the budget for the department of industry, commerce and enterprises in the assembly on Tuesday, industry minister **Tapas Roy** said the lease to ONGC — under the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025 — was for exploring a block covering 2,872.6sq km across Murshidabad, East Burdwan and Nadia.

"The state exchequer will



receive royalty and revenue in accordance with the executed revenue sharing contract," he said.

The minister added that a petroleum mining lease has been approved for ONGC's NELP block (WB-ONN-2005/4) in Ashoknagar field, spread over nearly 99 sq km in North 24 Parganas, for commercial extraction of crude oil and natural gas.

The Ashoknagar project

is expected to generate nearly Rs 104 crore in royalty for the state govt, putting Bengal on India's hydrocarbon production map. Commercial production from the Ashoknagar field will also elevate Bengal Basin from a Category III to a Category I sedimentary basin.

A Category III basin indicates presence of hydrocarbons without proven commercial production, while a Cate-

gory I basin signifies established commercial production of crude oil and natural gas.

While boosting Bengal's energy security, Roy said the twin initiatives will attract fresh investments in the upstream petroleum sector and create employment opportunities in exploration, production and associated industries.

Roy also informed the assembly on Tuesday that 798 km of gas pipelines was currently being laid under the City Gas Distribution (CGD) network by GAIL (India) Ltd, with active support from the state govt.

The projects, involving a cumulative investment of Rs 5,322 crore, are expected to expand the supply of piped natural gas to households, industries and commercial establishments while also facilitating the growth of CNG-based transport across urban centres in Bengal.



Publication : Business Standard	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 1, 4

PAGE 4

**W Asia war may
weigh on state-run
OMCs' margins**

State-run oil marketing companies (OMCs) are expected to report huge losses in Q1 as they absorb the full impact of the US-Iran war.

W Asia war may weigh on state-run OMCs' margins

SHUBHANGI MATHUR
New Delhi, 21 July

State-run oil marketing companies (OMCs) are expected to report huge losses in the April-June quarter as they absorb the full impact of the US-Iran war.

Driven by elevated energy prices, higher premiums and insurance costs, a weak rupee and delayed retail price hikes, OMCs might incur high losses in the first quarter of 2026-27 (Q1FY27), according to analysts.

State-owned OMCs comprise Indian Oil Corporation Ltd (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) and Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL). BPCL and HPCL are set to announce Q1FY27 results on July 22 while IOCL will announce quarterly earnings on July 31.

Oil companies' underrecovery on liquefied petroleum gas (LPG) is expected to average at ₹430 per cylinder while IOCL, BPCL and HPCL are likely to report losses of ₹18,570 crore, ₹12,400 crore and ₹12,500 crore, respectively, in the June quarter, said PL Capital in a report.

"Marketing margins are likely to remain weak due to elevated crude procurement costs, despite OMCs raising petrol and diesel prices by approximately ₹7.5 per litre in May '26. The impact was partly offset by ₹10 per litre excise duty cut and the GoI's (the government's) cap on domestic refinery transfer price (RTP) for MS (petrol) and HSD (diesel), which provided some cushion to underrecoveries," it added.

OMCs hiked fuel prices four times across the country in May, raising petrol prices by ₹7.38 a litre and diesel by ₹7.52

per litre. The companies incurred loss of ₹12 per litre on petrol sales and ₹32 per litre on diesel in Q1FY27, compared with a profit of ₹8 per litre on petrol and a loss of ₹1 per litre on diesel in Q4FY26, according to Emkay Global.

Crude oil prices averaged \$104 per barrel in the quarter but sharply corrected to around \$72 per barrel in June amid expectations of a ceasefire between the US and Iran.

Despite high gross refining margins (GRMs) in the quarter, the imposition of Special Additional Excise Duty (SAED) or windfall tax by the government on export of petrol, diesel and aviation turbine fuel (ATF) limited refiners' ability to fully benefit from stronger international refining cracks. Benchmark GRMs strengthened to \$25 per barrel in Q1FY27 from \$9 per barrel Q4FY26, supported by a spike in product cracks, said Emkay Global.

Revised fortnightly, the export duty on petrol currently stands at ₹2.5 per litre, while diesel and ATF exports attract levies of ₹15.5 per litre and ₹14.5 per litre, respectively. The government levied export duties to discourage exports and prioritise domestic fuel availability amid the West Asia crisis.

Rupee depreciation during the quarter further impacted the companies' performance in the quarter as the Indian currency weakened to ₹94.7 per dollar in Q1FY27 as against ₹91.5 per dollar in Q4FY26.

Private player Reliance Industries Ltd (RIL) reported a 30 per cent year-on-year (YoY) increase in revenue of its oil-to-chemicals (O2C) business during the



Pressure points

- Elevated crude prices, weak rupee, and delayed fuel price hikes may hit earnings
- LPG underrecovery seen at ₹430 per cylinder
- Fuel marketing margins remained under strain despite May price hikes
- Windfall tax limited gains from higher refining margins
- Crude averaged \$104 per barrel in Q1 before easing to \$72 a barrel

PL Capital estimates losses of...

IOCL	₹18,570 cr
HPCL	₹12,500 cr
BPCL	₹12,400 cr

June 2026 quarter, largely driven by a sharp increase in prices of crude oil, though partially offset by lower production meant for sale.



Q1
RESULTS
PREVIEW

Publication : Financial Express

Editions : New Delhi

Date :22 July 2026

Page : 1, 7

Houthi's Saudi blockade may hit oil bill

SAURAVANAND
New Delhi, July 21

INDIA'S CRUDE SUPPLIES and import bill may face a fresh shock after a Houthi threat to blockade Saudi Arabia put the kingdom's oil moving through Bab el-Mandeb at risk. The threat comes just as Saudi Arabian crude sharply regained share in India's import basket over the last two weeks.

Kpler data showed Saudi supplies to India rebounded

to 586,000 barrels per day (bpd) through July 19, doubling from 293,000 bpd for whole of June. The kingdom ranked third after Russia at 2.45 million bpd and the UAE at 617,000 bpd.

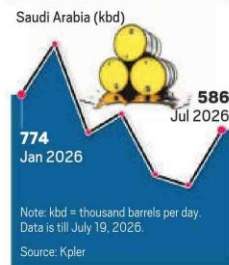
Saudi Arabia supplied India an average 700,000 bpd between July 2025 and April

2026, accounting for 14.5% of imports. Its share slipped to 7% in May-June before recovering to around 10% in July, increasing India's exposure to Riyadh's Red Sea route.

The threat comes as India's crude basket climbed to \$85.51 a barrel on July 20 from \$76.28 on July 13 and \$68.21 on July 3. Every \$10-a-barrel increase adds roughly \$42-million-a-day to India's crude import costs.

Continued on Page 7

RISING THREAT



Saudi blockade may hit oil bill

PRASHANT VASISHT, SENIOR vice-president and co-group head at Icria, said sustained disruption would hit India through freight, insurance and longer delivery times before shortages emerge. "For India, this would mean higher landed costs for crude oil, LPG, fertilisers and industrial inputs, alongside costlier exports and increased working-capital requirements," Vasisht said.

Riyadh has diverted about 70% of its energy exports through the Red Sea as Hormuz remains constrained. It is exporting 4 million bpd from Yanbu through its East-West pipeline, with nearly 2.5 million bpd moving south through Bab el-Mandeb, Rystad Energy vessel-tracking data showed.

"While the Houthis have not yet clarified how the blockade would be enforced, their previous campaign against commercial vessels demonstrates both the capability and willingness to disrupt Red Sea shipping," Jorge León of Rystad Energy said.

The threat currently appears confined to Saudi-linked shipping. Bab el-Mandeb operations remain normal and India's crude imports have not faced physical disruption, Kpler's Sumit Ritolia said.

"There is no immediate disruption to India's crude imports, with the current impact largely limited to higher freight, insurance costs and market volatility," Ritolia said.



India's risk would rise sharply if the threat spreads to wider Red Sea traffic. Russian shipments are expected to ease to 2.45 million bpd from 2.64 million bpd in June, but remain above the 12-month average of 1.73 million bpd. Russia, barely 2% of India's crude basket before February 2022, became its largest supplier between 2023 and 2025, contributing roughly one-third of imports.

Imports from Iraq, Kuwait and Qatar, whose exports rely on Hormuz, remain negligible and are unlikely to recover in late July after renewed US-Iran hostilities disrupted shipping.

"Any prolonged disruption would directly affect India's largest source of crude imports, increasing voyage times, freight costs and forcing refiners to seek more expensive alternative barrels," Ritolia said.

If tensions persist and the threat expands beyond Saudi-linked vessels, ships could avoid the Red Sea and reroute around

Africa's Cape of Good Hope, adding 10-14 days to transit schedules and increasing freight and insurance costs by 30-50%, an analyst said.

Vasisht said some oil cargoes redirected around Africa could face delays of up to a month. Longer voyages would consume more fuel, tie up vessels and reduce fleet availability.

"If Red Sea disruption coincides with constrained flows through the Strait of Hormuz, crude could climb back above \$100 a barrel and, under a severe scenario, move towards \$115-120," Vasisht said. The pressure would spread to inflation, the import bill, the current account and the rupee. "The risk for India is therefore not only a higher oil price, but also a more expensive, slower and less reliable supply chain," he said.

Oil prices have eased below \$88 from around \$91 as traders focus on Qatar's proposed ten-day ceasefire. Rystad

said the decline reflects diplomatic optimism, not improved supplies.

Two Indian state-run refiners have suspended crude oil loadings from Iraq as mounting security risks in the Strait of Hormuz make it increasingly difficult to ensure safety of vessels, according to people familiar with the matter.

Indian Oil abandoned plans to load the supertanker Lila Jamnagar, which can hold as much as 2 million barrels of oil, the people said, asking not to be identified because the matter is private. The refiner concluded it was too risky for a fully laden tanker to attempt a Hormuz crossing, after several freighters were struck by projectiles in recent days.

Mangalore Refinery & Petrochemicals, controlled by Oil and Natural Gas, has also suspended lifting from Iraq because of the deteriorating security situation, the people said.

Publication : Millennium Post	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 10

PSU OMCs spend over ₹1.72 lakh crore on ethanol procurement across 3 ESYs: Govt

'PSU OMCs procure fuel-grade ethanol from domestic sugarcane- and grain-based feedstocks under the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme'

NEW DELHI: Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs) spent Rs 48,757 crore on ethanol procurement during Ethanol Supply Year (ESY) 2023-24, Rs 73,996 crore during ESY 2024-25 and Rs 49,577 crore up to June in ESY 2025-26, the government informed Parliament on Monday.

In a written reply in the Rajya Sabha, Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi said PSU OMCs procure fuel-grade ethanol from domestic sugarcane- and grain-based feedstocks under the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme.

"OMCs procure ethanol from domestic sources, including sugarcane-based feedstocks such as C-heavy and B-heavy molasses, sugarcane juice and sugar syrup, as well as grain-based feedstocks including damaged foodgrains, surplus rice with the Food Corporation of India (FCI) and maize," the minister said.

The minister further informed that as of July 16, 2026, PSU OMCs had registered 501 ethanol manufacturing units for the supply of denatured anhydrous ethanol under the Ethanol Blended Petrol Programme.

"As on 16.07.2026, Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs) have registered 501 ethanol manufacturing units for supply of denatured



Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi further informed that as of July 16, 2026, PSU OMCs had registered 501 ethanol manufacturing units for the supply of denatured anhydrous ethanol under the Ethanol Blended Petrol Programme

anhydrous ethanol under the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme," Gopi said in the written reply.

According to the reply, Indian Oil Corporation Ltd (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) and Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), through its subsidiary HPCL Biofuels Ltd, are also engaged in the production of fuel-grade ethanol.

IOCL has an installed pro-

duction capacity of 228 kilolitre per day and produced 712 kilolitres in ESY 2025-26 up to June 30. BPCL has an installed capacity of 200 kilolitre per day and produced 76 kilolitres, while HPCL Biofuels has an installed capacity of 120 kilolitres per day and produced 9,373 kilolitres during the period.

The reply also showed that Uttar Pradesh recorded the highest sale of ethanol-blended

KEY POINTS

» IOCL, BPCL and HPCL, through its subsidiary HPCL Biofuels Ltd, are also engaged in the production of fuel-grade ethanol

» IOCL has an installed production capacity of 228 kilolitres/day and produced 712 kilolitres in ESY26 till June 30

» BPCL has an installed capacity of 200 kilolitres per day and produced 76 kilolitres

» HPCL Biofuels has an installed capacity of 120 kilolitres per day and produced 9,373 kilolitres during the period

petrol by PSU OMCs at 124.98 crore litres during ESY 2024-25, followed by Maharashtra at 110.66 crore litres, Tamil Nadu at 92.18 crore litres, Karnataka at 79.24 crore litres and Gujarat at 56.29 crore litres.

The government said the registered supplier base and domestic procurement network continue to support the implementation of the Ethanol Blended Petrol Programme across the country. ANI

CRUDE PAIN RETURNS

Oilmin Working Out Plan to Offset ₹75kcr OMC Loss

Cos seek financial support; finmin nod must before sending proposal on relief package to cabinet

Sanjeev Choudhary

New Delhi: The oil ministry is working on a proposal to compensate state-run oil marketing companies (OMCs) after they sought relief for losses of about ₹75,000 crore incurred in the April-June quarter from selling fuel below market rates, according to people familiar with the matter.

Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp and Hindustan Petroleum Corp have largely sold petrol, diesel and LPG below market rates since February 28, when the US-Iran war broke out. After a truce pulled benchmark Brent crude down to about \$71 a barrel, the companies had hoped to recover their losses before considering any cut in pump prices.

Those hopes have faded as crude has climbed back above \$90 a barrel amid renewed West Asia conflict. The companies have told the government that the losses are too large to absorb without urgent financial support, people aware of the discussions said.

Distress Call

OMCs have sold fuel and LPG below market rates since onset of Iran war in Feb

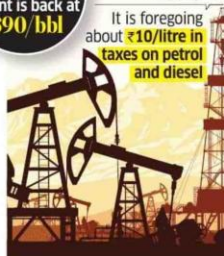


IOC, BPCL and HPCL seek relief, say losses too large to bear

Centre may resist a big payout

Hopes to recoup losses dashed as Brent is back at \$90/bbl

It is foregoing about ₹10/litre in taxes on petrol and diesel



The proposal will require the finance ministry's approval before being placed before the cabinet and is likely to involve weeks or even months of inter-ministerial negotiations, the people said. For the government, which is already foregoing about ₹10 per litre in uncollected taxes on petrol and diesel, agreeing to a large compensation package could prove difficult.

Deregulation Principle ➤ 9

Publication : The Economic Times	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 1, 9

Deregulation Principle

» From Page 1

Earlier this month, oil minister Hardeep Singh Puri said the three OMCs had incurred losses of ₹74,781 crore during the April-June quarter. The final figure will become clearer as the companies begin reporting quarterly earnings this week.

The government has historically treated losses on LPG differently from those on petrol and diesel. While LPG remains a regulated fuel, petrol and diesel are officially deregulated, even though state-run OMCs have largely aligned pump prices with government expectations.

The Centre provided ₹22,000 crore in 2022 and ₹30,000 crore last year to compensate OMCs for selling LPG below cost. However, it has been reluctant to compensate losses on petrol and diesel in recent years because doing so would undermine the principle of deregulation and could trigger similar claims from private fuel retailers.

In the February 2023 budget, the government instead proposed a ₹30,000 crore equity infusion into the OMCs after they sought compensation for petrol and diesel losses.

The companies saw little value in additional government equity instead of direct compensation. As crude prices subsequently eased and OMCs recovered much of their losses, the government dropped the equity infusion proposal.

Publication : The Hindu	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 16

GAIL Inks Pact with KABIL to Strengthen Collaboration in Critical Minerals

GAIL (India) Limited signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Khanij Bidesh India Limited (KABIL) today to collaborate in the field of critical and strategic minerals, supporting India's long-term resource security. The MoU has been signed by Shri Sanjeev Kumar, Executive Director (R&D & E&P), GAIL, and Shri Sunil Kumar Singh, Chief Executive Officer, KABIL, in the presence of Shri R. K. Singhal, Director (Business Development), GAIL, and other senior officials from both the organizations. The partnership provides a framework for cooperation in identifying and evaluating opportunities in critical and strategic minerals, facilitating the exchange of technical expertise, capacity building, and exploring joint initiatives across the mining value chain to help strengthen India's long-term supply of these vital resources and clean energy transition.

Indian Oil Corp said to cancel Iraq oil lifting amid attacks

Reuters
NEW DELHI

Indian Oil Corp has cancelled the lifting of Iraqi oil from Basrah Oil Terminal due to increased risk and attacks on some vessels transiting through the Strait of Hormuz, three sources familiar with the matter said.

State-run IOC was preparing to lift 2 million barrels of Iraqi oil in the very large crude carrier Lila Jamnagar around July 23.

Another cancellation

Another state refiner, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd., also cancelled plans to lift oil from Iraq in the Indian-flagged Aframax tanker Desh Garav, they said.

The two Indian refiners



IOC was preparing to lift 2 million barrels in the very large crude carrier Lila Jamnagar

did not immediately respond to a *Reuters* request for comment.

India has advised shipowners, ship managers and recruitment companies not to deploy the country's seafarers on vessels undertaking trips through the Strait of Hormuz following the resump-

tion of fighting in the region.

The shipping regulator has also directed masters of vessels to ensure that they are sufficiently vigilant about the security situation in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and adjoining waters, and called for continuous monitoring of navigational warnings.

The Strait of Hormuz between Iran and Oman was the main transit route before the conflict for around a fifth of global energy supplies.

Tensions have escalated since a fragile truce between Washington and Tehran collapsed in early July, reviving heavy exchanges of strikes and further disrupting shipping through the waterway.

‘India signed 8.4 mtpa of long term LNG contracts’

Rishi Ranjan Kala
New Delhi

India was the “most active” buyer for long term contracts of liquefied natural gas (LNG) in the 2025 calendar year, contracting 8.4 million tonnes per annum (mtpa) capacity, said the International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL).

GIIGNL’s 2026 annual report pointed out that the last calendar was an exceptionally active year for LNG contracting, with 83 long-term sale purchase agreements (SPAs) signed, nearly double the 47 recorded in 2024, and disclosed volumes reaching 71.6 mtpa across 76 agreements, a roughly 30 per cent increase over the previous year.

It also noted that demand growth, portfolio management, and strategic procurement shaped the buyer landscape in 2025.

END-USER BUYER

“India was the most active end-user buyer, with 8.4 mtpa disclosed across six entities, including Indian Oil Corporation (4.7 mtpa), GAIL (1 mtpa), Gujarat State Petroleum Corporation (1 mtpa), Torrent Power (0.69 mtpa), Bharat Petroleum Corporation (0.5 mtpa), and Hindustan Petroleum Corporation (undisclosed), reflecting a coordinated expansion of long-term import

India was the most active end-user buyer, with 8.4 mtpa disclosed across six entities

capacity driven by rising domestic gas demand,” the international group of LNG importers said.

GIIGNL said that short-term SPA activity also rose from 7 to 13, while Heads of Agreement (HOA) activity declined from 21 to 12.

MARKET IMPACT

This surge reflects the convergence of two structural forces—sustained demand growth across key importing markets, and an ongoing wave of liquefaction projects seeking offtake commitments to reach final investment decision (FID), it added.

The GIIGNL report pointed out that attack on Qatar’s Ras Laffan liquefaction terminal and one of the two trains of Pearl Gas-to-Liquid (GTL) plant can lead to a wider market impact.

“Ras Laffan is the backbone of Qatar’s gas export system, and the confirmed LNG capacity loss is already significant. However, the wider market impact could be greater because Pearl GTL is integrated into the same gas and industrial network,” it added.

Publication : Business Standard	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 7

Doval discusses energy security, regional situation with Saudi FM

National Security Advisor Ajit Doval visited Saudi Arabia and held talks with Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan on strengthening "energy security" and protection of "maritime corridors."

The visit comes amid renewed tensions between Iran and the US, with concerns over disruptions to key shipping routes and energy supplies.

According to the Saudi Foreign Ministry, Doval met Prince Faisal in Riyadh on Monday. The two sides reviewed bilateral relations and discussed ways to strengthen the strategic partnership between the two countries. This is Doval's third visit to Saudi Arabia

this year.

"They also discussed the latest regional developments and the efforts to enhance energy security and protect maritime corridors," the ministry posted on X. The meeting was also attended by Saudi Deputy Minister for Political Affairs Saud Al-Sati.

Doval's visit comes amid heightened tensions in the region after Yemen's Iran-backed Houthi rebels announced a "maritime embargo" against Saudi Arabia, saying they would block Saudi vessels in the Bab al-Mandab Strait in retaliation for what they described as Riyadh's blockade of ports and airports in Houthi-controlled areas of Yemen. p71

Publication : Business Standard	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 22

No proposal to return to ethanol-free petrol: Govt

Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi has said there is no proposal to revert to either ethanol-free petrol or petrol with 10 per cent ethanol, as E20 petrol has been scientifically validated and accepted by the automobile industry after extensive testing.

"The objective of public policy is to move forward with a superior fuel, not return to an inferior standard," he said in a written reply in Parliament, responding to a question on whether the government proposes to continue supply of pure petrol (E0 or E10) for vehicles not designed for E20 fuel.

He added that maintaining parallel nationwide supply chains for E0, E10, and E20 petrol across more than 100,000 retail outlets

would significantly increase logistics complexity, inventory, and handling costs.

He said that the government has not received any widespread or substantiated complaints regarding vehicle performance attributable to the use of E20 petrol, but has taken note of certain media reports and social media posts, and these concerns have been scientifically examined.

"E15+ blended petrol has been in widespread use across the country for over three-and-a-half years and E19-E20 fuel for over two-and-a-half years, with over 200 million two-wheelers and over 30 million petrol cars operating on these blends without any verified evidence of widespread engine failure attributable to E20 fuel," Gopi said. BS REPORTER

Publication : Business Standard	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 4

Oil prices, weak monsoon pose biggest risks to India's FY27 GDP growth: IMF

India's gross domestic product (GDP) growth in 2026-27 (FY27) faces key downside risks from a widening war in West Asia that is driving up oil prices and a monsoon weakened by the El Niño weather effect, an International Monetary Fund (IMF) official said.

Asia's third-largest economy imports almost 80 per cent of its oil needs, making it vulnerable to energy shocks that could hurt growth and stoke inflation.

The Fund cut India's GDP growth forecast for FY27 by 10 basis points to 6.4 per cent this month, while raising its FY28 forecast by 20 basis points to 6.7 per cent.

"The downside risks are probably twofold," Ranil Salgado, IMF's senior resident representative for India and

Bhutan, told *Reuters*.

"One is that the war is already starting to expand again, and that has implications for oil prices." However, this month's IMF projections did not fully reflect the impact of a weak monsoon, Salgado said.

"This is an El Niño year that could lead to a poor monsoon," he added "We had a delayed monsoon, some recovery in July, but we will have to see how that plays out."

Salgado said the IMF would also reassess the quality of India's national accounts this year after the statistics department releases the back series based on the revised 2022-23 GDP base year, expected towards the year-end.

REUTERS



Saudi tankers turn back after Houthi threat

The two vessels were bound for China and India; Iranian forces target US sites in Gulf and Jordan

REUTERS
21 July

Two oil tankers carrying Saudi crude to Asia reversed course in the Red Sea on Tuesday after threats from Yemen's Iran-aligned Houthis, as a widening West Asia conflict disrupted shipping through two of the world's most critical energy chokepoints.

The diversions came as US forces bombed targets in the south and west of Iran overnight, Tehran targeted US sites in Bahrain, Kuwait and Jordan and at least one tanker was hit in the Strait of Hormuz in the latest escalation of violence that has all but wrecked an interim peace deal signed last month.

The Houthis announced a naval blockade on Saudi Arabia on Monday, opening a potential new front in the war and raising the threat to global energy supplies and trade beyond the Gulf.

The two tankers, which loaded Saudi crude bound for China and India this week, made U-turns and were headed toward the Suez, shipping data on LSEG showed. However, sources said Saudi Arabia's Red Sea port of Yanbu was operating normally.

Oil prices gained around 2 per



Kuwaiti PM Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah visits an injured person at a hospital following the Iranian attacks

cent on the latest attacks, but signs that Tehran and Washington want to resume diplomacy helped to limit price rises.

US Central Command said it had hit Iranian military command centers, maritime capabilities, missile and drone launch sites, and air defence systems in its latest round of strikes.

Explosions were heard around the city of Shiraz in southern Iran, state media said. Konarak and Chabahar on the southern coast, the city of Khorramabad and a civilian site outside the city of Ab-

dan, both in the west, all came under attack, media reports said. Later the IRNA news agency quoted an official in Khorramabad as saying no enemy attack had taken place there.

Fifty civilians have been killed and 500 wounded in the recent US strikes on Iran, a health ministry official said.

Iran launched renewed attacks across the Gulf, where recent strikes on desalination facilities have raised concerns about water shortages. Kuwait said it was responding to a drone

and missile attack on Tuesday afternoon and sirens sounded in Bahrain. Attacks on Kuwaiti power generation and water desalination plants on Monday forced several generation units out of service as a precaution and repairs were underway, authorities said.

Iran's Revolutionary Guards said they targeted infrastructure in Bahrain belonging to US tech company Amazon in response to what they described as a US strike on the construction site of Iran's planned Darkhovin nuclear power plant.

Iranian state media reported that Iranian forces also targeted accommodation facilities of US military personnel at Bahrain's Sheikh Isa Air Base. There was no immediate comment from the US military, Bahrain or Amazon on the reported incidents, which Reuters was unable to verify.

The Iranian army said it launched drone attacks against three US military bases in Kuwait on Tuesday. The Guards said they attacked a US military site in Jordan, while Jordan said its forces intercepted and destroyed five Iranian drones.

The maritime security agency UKMTO said on Tuesday a tanker

in the Strait of Hormuz reported being struck by a projectile, forcing its crew to abandon the vessel and board a lifeboat. Iran's Revolutionary Guards also said two oil tankers caught fire after explosions while attempting to transit the southern shipping lane of the strait, through which one-fifth of global oil and liquefied natural gas supplies normally pass.

The war has killed thousands of people, mostly in Iran and Lebanon. Parts of Lebanon remain under Israeli occupation. Israeli troops have withdrawn from parts of southern Lebanon under a US-mediated ceasefire agreement, which aims to keep Iran-backed Hezbollah away from the Israeli border and end nearly five months of conflict. The move comes after Lebanese President Joseph Aoun traveled to Washington for a meeting with US President Donald Trump on Tuesday. At the meeting, Trump said that Lebanon had been hit hard for decades and that the United States would help the country going forward. "It's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated, and treated with the respect that it deserves," he said.

Publication : Business Standard	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 4

Reliance, Nayara boost June crude oil imports

The country's major private refiners, Reliance Industries and Nayara Energy, increased crude oil imports in June, with Reliance halting purchases from Iraq while Nayara continued to rely exclusively on Russian supplies, according to trade and industry data.

Reliance, which operates the world's largest refining complex, imported about 1.32 million barrels per day (bpd) of crude in June, up 15.6 per cent from the previous month. The firm did not import any Iraqi crude during the month. It also resumed imports from Saudi Arabia after a month's gap, receiving crude shipped from the Kingdom's Red Sea port of Yanbu.

Meanwhile, Nayara Energy, part-owned by Russian oil major Rosneft, imported 395,310 bpd of Russian crude in June, an increase of 16.2 per cent from a year earlier. The 400,000-bpd Vadinar refinery in Gujarat has been processing only Russian crude after Nayara's other suppliers — Iraq's SOMO and Saudi Aramco — stopped supplies. REUTERS

Iran, US exchange attacks as Pakistan tries to salvage ceasefire deal

Iran strikes
US allies across
West Asia

ISLAMABAD, AP/PTI

Diplomats sought on Tuesday to salvage the collapsed interim deal between Iran and the US even as both countries continued launching attacks on the 10th day of renewed fighting. Iranian Interior Minister Eskandar Momeni's visit to Pakistan, a key mediator in the conflict, pointed to in-

Trump talks of targeting
underground N-complex

President Donald Trump said on Tuesday the US was far from finished with Iran and warned the next US military target could be an underground nuclear complex known as Pickaxe Mountain, AFP reports from Washington. Pickaxe Mountain is a deeply buried nuclear site near Natanz where Western intel suspects Iran is building an enrichment facility. "We'll be hitting that area pretty soon, and very heavily," Trump said, adding that he would not normally announce targets but "there's not a thing they can do about it."

tensified diplomatic efforts, but it remained unclear what new arrangement might be reached to end the war.

Shipping through the Strait of Hormuz has largely stalled, and as the fight for control of the waterway intensifies, both

sides have targeted civilian infrastructure relied upon by millions of people.

A barrage of US strikes has not compelled Tehran to loosen its grip on the strait, through which about one fifth of the world's crude oil and natural gas was shipped before the war.

The US continued its air strikes on the Islamic Republic early on Tuesday, and Iran attacked a tanker in the strait, forcing the crew to abandon the ship.

Iran also kept up its attacks against US allies, and on Tuesday afternoon, sirens in Bahrain and Kuwait warned residents of incoming projectiles.

LPG cylinder a tap away, but proceed with caution

A fire safety expert shares tips as quick delivery targets young, first-time users

RASHMI RAJAGOPAL
TEAM METROLIFE

Last week, quick commerce app Swiggy announced its partnership with Hindustan Petroleum Corp Limited (HPCL) to launch gas supply services through its grocery delivery platform Instamart. Currently being piloted in Bengaluru, consumers can order 5 kg and 10 kg LPG cylinders through the service.

The easy access to cooking gas is seen as a boon by many, especially following the gas crisis brought on by the West Asia conflict. However, some have reservations regarding its safety, given that it is being targeted at students and young working professionals.

Metrolife spoke to Subhash Kumar, a fire safety expert, for quick tips on safe handling of LPG cylinders.

First of all, one must ensure the way the cylinders are being stored is safe, says Subhash. Dark stores are located near office buildings and residential neighbourhoods. If they are being mis-handled and there is an explosion or leakage, it affects not just the storage space, but also those in the vicinity, he explains. Given that this will make LPG cylinders easily accessible to young students, who have probably never handled



While the service is seen as a boon, it has raised safety concerns.

them before, they must be aware of how to handle leaks, he notes.

"One can check if there is a leak when the cylinder is delivered by pouring some water on the brass opening after the plastic cap is opened. In case the

water bubbles, it suggests that there is a leak," he points out.

Check date

Secondly, one must look for the date the cylinder was manufactured. The lifespan of a cylinder is eight years. Anything older should ideally be replaced. "Empty cylinders are handled without care. They are often thrown when being loaded or unloaded. Even while being transported, the metal bodies collide with each other, resulting in damage which gets worse over the years," Subhash explains.

The date is usually printed at the top of the cylinder and is indicated by an alphabet and the last two digits of the year it was made. Each alphabet corresponds with a quarter of the year — A stands for the first quarter, B for the second and so on. So, the manufacturing date could look something like C 20, meaning it was manufactured in the third quarter of 2020.

In case of leaks

If one can smell leaking gas, the most obvious step is to open all the windows and ensure the space is well ventilated. Alternatively, move the cylinder to a terrace, balcony or an open space. "Do not take your smartphone near the area of the leak and do not use any electrical equipment. The gas permeates the narrowest of spaces and even a small spark could result in an explosion," he shares.

In case of a fire, do not try to extinguish it with water. Instead, use a thick cloth or a wet bedsheets. One can also use loose sand if it is easily available, he adds.

India needs \$22.7 trn to achieve net zero by 2070

SAURAV ANAND
New Delhi, July 21

INDIA WILL REQUIRE an estimated \$22.7 trillion, or about ₹2,167 lakh crore, in cumulative investment by 2070 to achieve its net-zero target, but faces a projected financing gap of \$6.5 trillion, or around ₹620 lakh crore, highlighting the need for stronger corporate climate-transition disclosures, according to the Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

International finance may have to meet up to 42% of the country's total investment requirement. IEEFA said lenders and investors are increasingly using transition-plan credibility to price risk, allocate capital and determine long-term access to domestic and global financing. Companies unable to present comparable and verifiable plans could risk losing access to capital.

The institute has proposed

BUILDING ROAD MAP

■ The country faces a projected financing gap around **₹620 lakh cr.**, highlighting the need for stronger corporate climate-transition disclosures

■ Investors are using transition-plan credibility to price risk, allocate capital and determine long-term access to domestic, global financing

■ IEEFA has proposed a 2-phase strengthening of the Business Responsibility and Sustainability Reporting framework

■ Globally, 139 of 198 countries and 1,276 of 1,987 firms tracked by Net Zero Tracker had set net-zero targets as of May 2026



a two-phase strengthening of the Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) framework. The first phase would introduce a short transition-plan snapshot that reorganises information already required under BRSR or voluntarily disclosed by companies into a standardised, comparable format.

IEEFA said the snapshot could initially be mandatory for companies in high-emitting

sectors such as power, steel, cement, oil and gas, chemicals and commodities among the top 500 listed firms by market capitalisation. Other companies in the top 500 could adopt it voluntarily before mandatory coverage is extended to all top 1,000 BRSR-reporting entities.

The second phase would add 23 priority metrics to BRSR. A first batch of 13 would cover net-zero ambition, short-term emission targets, transition levers,

capital expenditure allocation, scenario analysis, board oversight, internal carbon pricing and climate-risk integration.

A second batch would deepen disclosures on medium-term targets, green or low-carbon revenue, transition-financing sources, Scope 3 emissions, climate-linked incentives, value-chain engagement and workforce reskilling.

The roadmap runs from FY27 to FY32. The short-term

phase covers FY27-FY28, the medium term FY29-FY30 and the long term FY31-FY32, giving companies time to strengthen data systems, governance and assurance practices.

The proposal builds on BRSR Core, whose assessment or assurance obligations are set to cover the top 1,000 listed companies by FY27.

IEEFA's recommendations follow an assessment of 33 Indian companies across six

high-emitting sectors using 77 metrics. It found that BRSR provides a strong sustainability-reporting base but remains largely backward-looking and does not adequately connect climate targets with capital expenditure, revenues, funding and risk management.

The report also flagged weak scenario analysis, inadequate Scope 3 coverage, limited assurance and insufficient accountability or climate-linked incentives. Disclosure quality varied sharply with company size and investor visibility, leaving a small group of leaders and a wider base of compliance-driven reporters.

Globally, 139 of 198 countries and 1,276 of 1,987 companies tracked by the Net Zero Tracker had set net-zero targets as of May 2026. IEEFA said embedding transition planning within BRSR could improve comparability and capital access without creating a separate disclosure regime.

Headline: Green energy generation crosses 100 GW

हरित ऊर्जा उत्पादन 100 गीगावाट के पार

उपलब्धि

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में पहली बार हरित ऊर्जा का उत्पादन 100 गीगावाट के पार पहुँच गया है। इस माह 13 जुलाई को सौर और पवन ऊर्जा की कुल बिजली में हिस्सेदारी भी 42.79% तक पहुँच गई। ग्रिड कंट्रोलर के आंकड़े से यह खुलासा हुआ है।

ग्रिड कंट्रोलर के आंकड़ों के अनुसार, 13 जुलाई को दोपहर 12 बजकर 5 मिनट पर सौर और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन 103.7 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा। इससे एक दिन पहले शाम को पवन ऊर्जा उत्पादन भी सर्वाधिक 36.6 गीगावाट दर्ज किया गया। भारत ने यह उपलब्धि ऐसे वक्त में हासिल की है जब देश में बिजली की मांग में लगातार

ऊर्जा भंडारण और सुधार प्राथमिकता



अब अगला चरण ऊर्जा भंडारण, ग्रिड की लचीलापन क्षमता, ट्रांसमिशन नेटवर्क और बिजली बाजार में सुधार पर केंद्रित होगा।

बढ़ोत्तरी हो रही। इस साल भीषण गर्मी, लंबे हीटवेव और एयर कंडीशनर समेत अन्य उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल से बिजली मांग दो बार 270 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर तक पहुँची।

25 अप्रैल को जब बिजली की मांग 270 गीगावाट तक पहुँची, तब सौर ऊर्जा ने पीक डिमांड के दौरान 57

नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन आफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रह्मण्यम पुलिपाका के मुताबिक यह उपलब्धि कई वर्षों के निवेश, ट्रांसमिशन नेटवर्क, बिजली पूर्वानुमान और ग्रिड संचालन में हुए सुधारों का परिणाम है। उनका कहना है कि

गीगावाट और दोपहर में 81 गीगावाट बिजली उपलब्ध कराई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल से अब तक कुल बिजली आपूर्ति में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी 35 से 42 प्रतिशत के बीच रही है। अगर जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा को भी शामिल कर लिया जाए, तो

बिजली व्यवस्था में बदलाव

ऊर्जा संस्था अंबर के वरिष्ठ विश्लेषक नेश्विन रोड्रिग्स इसे भारत की बिजली व्यवस्था में एक संरचनात्मक बदलाव मानते हैं। उनके अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी अब पारंपरिक बिजली उत्पादन की पूरक नहीं रह गई है, बल्कि देश की बढ़ती बिजली मांग पूरी करने का प्रमुख स्रोत बनती जा रही है। हालांकि, वे चेतावनी देते हैं कि अब ऊर्जा भंडारण, ट्रांसमिशन और ग्रिड लचीलेपन पर तेजी से निवेश करना होगा।

गैर-फॉसिल फ्यूल स्रोतों की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत तक पहुँच जाती है।

भारत के लिए यह रिन्यूएबल एनर्जी का एक ऐतिहासिक वर्ष है। देश का बिजली ग्रिड अब 100 गीगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी को बिना किसी बड़ी बाधा के संभालने में सक्षम साबित हुआ है।

Publication : Hindustan (Hindi)	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 6

Headline: Oil companies have bought ethanol worth millions

तेल कंपनियों ने करोड़ों का इथेनॉल खरीदा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान एथनॉल खरीद पर 1.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने लिखित उत्तर में बताया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां घरेलू स्तर पर गन्ना और अनाज आधारित कच्चे माल से उत्पादित ईथन-ग्रेड एथनॉल को खरीद करती हैं।

Publication : Hindustan Times	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 1, 15

Oil at 5-wk high on Iran strikes, Houthi threats

Reuters

letters@hindustantimes.com

DUBAI: Two oil tankers carrying Saudi crude to Asia reversed course in the Red Sea on Tuesday after threats from Yemen's Iran-aligned Houthis, as a widening Middle East conflict disrupted shipping through two of the world's most critical energy chokepoints.

US forces bombed targets in the south and west of Iran overnight, while Tehran targeted US sites in Bahrain, Kuwait and Jordan and a tanker was hit in the Strait of Hormuz. Oil prices climbed about 2% on Tuesday to a five-week high, on worries that energy supply disruptions could worsen in the Middle East. Brent futures rose \$1.83, or 2.1%, to

continued on →15

Publication : Hindustan Times

Editions : New Delhi

Date :22 July 2026

Page : 1, 15

IRAN-U.S. WAR

\$91.05 a barrel at 1.26 pm EDT (1726 GMT), while U.S. West Texas Intermediate crude gained \$1.92, or 2.3%, to \$85.15.

Iran said it had struck infrastructure belonging to Amazon in Bahrain. The Houthis, who control northern and western Yemen including the coast at the mouth of the Red Sea, announced a naval blockade on Saudi Arabia on Monday, opening a potential new front in the war. In a letter to shippers, they threatened to attack any ships that load or discharge Saudi oil.

US President Donald Trump said the Houthis had not yet shut the Bab el-Mandeb, the "Gate of Tears" strait leading into the Red Sea, and threatened to act against them if they did. "So far it hasn't happened. Might happen, but we take care of things. If something like that happens, we take care of it," Trump said.

But the Houthi announcement already appeared to be having an impact. Two tankers which had just loaded Saudi crude bound for China and India at Saudi Arabia's Red Sea port of Yanbu made U-turns on Tuesday, heading towards the Suez Canal rather than out through the Bab el-Mandeb into the Indian Ocean. With the war shutting the Strait of Hormuz leading out of the Gulf, the Red Sea has served as the main alternate route out for millions of barrels of Saudi oil per day, diverted by pipeline through Yanbu.

US Central Command said it had hit Iranian military command centres, maritime capabilities, missile and drone launch sites and air defence systems in its latest round of strikes, which have carried on nightly for more than a week and a half. Explosions were heard around the city of Shiraz in southern Iran, state media said. Konarak

and Chabahar on the southern coast, the city of Khorramabad and a civilian site outside the city of Abadan, both in the west, all came under attack, media reports said. Later the IRNA news agency quoted an official in Khorramabad as saying no enemy attack had taken place there.

Fifty civilians have been killed and 500 wounded in the recent US strikes on Iran, a health ministry official said. Washington has reported three US soldiers killed in recent days in the region and says it is punishing Iran for their deaths.

The US and Iran have been testing the limits of escalation since the collapse this month of a weeks-old interim deal to halt fighting. Iran launched renewed attacks on Tuesday across the Gulf, where recent strikes on desalination facilities have raised concerns about shortages in desert countries that depend almost entirely on removing salt from seawater for potable supplies. Kuwait said it was responding to a drone and missile attack on Tuesday afternoon. Kuwait has reported attacks that have damaged power generation in recent days at plants that also produce fresh water.

Sirens sounded in Bahrain where Iran's Revolutionary Guards said they targeted infrastructure belonging to Amazon, in response to what they described as a US strike on the construction site of a planned Iranian nuclear power plant.

Iranian state media reported that Iranian forces also launched attacks on U.S. military barracks in Bahrain and bases in Kuwait and Jordan. The maritime security agency UKMTD said on Tuesday a tanker in the Strait of Hormuz reported being struck by a projectile, forcing its crew to abandon the vessel and board a lifeboat. Iran's Revolutionary Guards also said two oil tankers had caught fire after explosions while attempting to transit the southern lane of the strait.

A senior Iranian official told Reuters on Monday that Tehran had received a proposal from mediators for a 10-day ceasefire in efforts to salvage the interim deal, intended to pave the way to a lasting deal to end the war that began on February 28. Iran's Interior Minister Eskandar Momeni visited mediator Pakistan and asked Islamabad to continue its efforts.

Trump, hosting the president of Lebanon at the White House, said the Iranians "want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest."

Publication : Mint	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 2

India's RE installed capacity reaches 288.58GW: Naik

New Delhi: India's renewable energy installed capacity has increased from 76.38GW in 2014 to 288.58GW by June 2026, Parliament was informed on Tuesday. The 288.58 GW includes 162.15 solar, 57.44 wind energy, 11.75GW bio power and 57.24GW hydro power. Minister of state for new & renewable energy Shripad Yesso Naik stated told Rajya Sabha that from FY14 to FY26, renewable energy sector in the country has attracted foreign direct investment of \$45.72 billion.

PTI

Publication : Mint	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 2

Oil prices, weak rains risks to FY27 GDP growth: IMF

REUTERS



New Delhi: India's GDP growth in 2026-27 faces key downside risks from a widening West Asia war that is driving up oil prices and a monsoon weakened by El Niño, Ranil Salgado, the International Monetary Fund's (IMF's) senior resident representative for India and Bhutan, told *Reuters* in an interview on Monday. IMF cut India's GDP growth forecast for 2026/27 to 6.4% this month. **REUTERS**

Publication : Mint	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 1



Publication : Mint	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 12

Adani-Total Gas Q1 profit falls 18% on higher gas price

Adani Total Gas Ltd, the city gas joint venture of Adani Group and TotalEnergies of France, on Tuesday reported an 18% drop in June quarter profit as the price of gas soared in the aftermath of the West Asia crisis.

Net profit of ₹133 crore in April-June—the first quarter of the current 2026-27 fiscal year—compared with ₹162 crore earning in the same period a year back, the company said in a statement.

Revenue was up 27% at ₹1,910 crore on account of higher volumes of compressed natural gas (CNG).

The cost of natural gas, which is turned into CNG to run automobiles and piped to household kitchens for cooking, rose 39% to ₹1,454 crore.

"Higher gas cost due to continued West Asia crisis, and increase in APM (administered price mechanism) gas price ceiling, the cost of natural gas rose 39%," the statement said.

PTI

Publication : The Economic Times	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 1, 13

Auto Inc Calls for System to Prevent E20 Contamination



The auto industry has urged the oil ministry to devise a formal system to detect contamination at

pumps, reports **Sharmistha Mukherjee**. There are increasing reports of worsening vehicle performance since ethanol blending rose to 20%. Stalling vehicles have revealed elevated chloride and moisture levels. **►► 13**

AMID GROWING CONCERNS OVER CONTAMINATED PETROL...

Carmakers Call on Govt to Test Fuel Quality at Pumps

Want an independent body to test the fuel at pumps and certify that it meets BIS specifications

Sharmistha Mukherjee

New Delhi: The automobile industry has urged the oil ministry to devise a formal mechanism for detecting contamination at petrol pumps across the country amid growing concerns over fuel quality. This follows drivers increasingly reporting worsening vehicle performance since the government raised ethanol blending in petrol to 20% under the E20 programme.

Auto industry executives said E20 fuel itself isn't harmful to compliant vehicles, emphasising that the real issue is of adulterated or contaminated fuel reaching consumers.

Investigations triggered by complaints of stalled or non-starting vehicles repeatedly revealed elevated chloride and moisture levels in the petrol supplied. Given this, carmakers are calling for an independent body to test and certify fuel quality at pumps, ensuring what's dispensed matches the prescribed standards and doesn't damage engines. Fuel pump owners too have been highlighting the issue of contaminated petrol.

"The maker can't be the checker," a senior industry executive said, requesting anonymity. "At present, oil marketing companies (OMCs) check the quality of fuel being dispensed at pumps. An independent body needs to be made responsible to examine whether the fuel being retailed meets the specifications outlined by BIS."

Mix & Match

HOW CONTAMINATION OCCURS

- Ethanol absorbs water from its surroundings
- Water can enter through rain or condensation
- Excess water triggers ethanol phase separation
- Existing tanks were built for conventional petrol
- Tanker deliveries may also introduce moisture
- Water-ethanol settles below petrol in tanks

VEHICLES MAY RECEIVE CONTAMINATED BOTTOM-LAYER FUEL



Bureau of Indian Standards (BIS) norms states there should be "no addition of detergents, dispersants, silicon, chlorine containing additives, materials and metallic additives" in E20 fuel. India mandated sales of E20 petrol nationwide from April. Several consumers since have complained of falling fuel efficiency and, in some cases, damage to non-compliant vehicles. The government and industry have dismissed claims that E20 has harmed vehicles.

"The quantum of ethanol being blended in petrol has doubled to 11 billion litres in the last two years," said a second industry executive. "But while the ratio of ethanol in the fuel has increased, the infrastructure remains the same. Trucks which were used in alterna-

te applications are carrying E20 fuel; depots and fuel storage tanks at petrol pumps have not been upgraded. Therefore, the instances of fuel contamination."

Ethanol is hygroscopic or has an affinity to water. Since the existing underground tanks and pipelines were designed to carry conventional petrol, higher ethanol blends can result in contamination of E20 stocks. Insiders said underground tanks that store fuel often have some amount of water due to ingress during rain or moisture or condensation or from the fuel tanker that brings petrol to the outlet.

When water content in the E20 stock in underground tanks exceeds 0.5%, ethanol binds with water due to its hygroscopic nature. This results in phase separation, where water-ethanol mixture settles at the bottom of the tank, while the petrol forms a separate layer on the top. When petrol is drawn from underground tank, vehicles may get the water-rich mixture from the tank's bottom instead of E20 fuel, causing them to break down or fail to start.



Investigations triggered by complaints of stalled vehicles revealed elevated chloride and moisture levels in the petrol supplied

Publication : The Economic Times	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 11

Crude Prices, Reduced Capital A/C Support Impacted Rupee: FM



The rupee depreciation against the dollar in recent months has been influenced by several factors, including reduced support from the capital account amid rising crude oil prices in the wake of the conflict in West Asia, the Rajya Sabha was informed on Tuesday. Finance minister Nirmala Sitharaman said in a statement that while the currency depreciation will likely bolster export competitiveness, thus impacting the economy positively, it may also raise prices of imported goods. Besides the exchange rate, the import bill is also determined by several factors, including global supply-demand conditions, geopolitical developments, domestic demand, and factors. Global value chain integration necessitating imports of intermediate goods for production and exports, and international prices of imported products, too, weigh on a country's import bill, she said. The rupee ended up 12 paise at 96.24 a dollar on Tuesday, thanks mainly to the West Asia war.

UN Climate Chief Lauds India's Renewable Push

During his India visit, the UNFCCC chief held talks on COP31, climate finance and technology transfer

Urmi Goswami

New Delhi: UN climate chief Simon Stiell is in India to "get a deeper understanding" of the "incredible progress" on the country's energy transition, its electrification programmes and "significant rollout" of renewables.

"India's clean energy growth is like Sachin Tendulkar and Vaibhav Sooryavanshi...rolled into one: a stellar record. But the story is just getting started — and if India keeps doubling down on renewables and clean tech, the next chapters promise to be truly extraordinary," said Stiell, executive secretary of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

In Delhi, Stiell met with ministers and key officials from the ministries of environment, power, new and renewable energy, and external affairs, as well as business leaders. "The discussions have ranged from outlooks to the preparations for COP31 in terms of expectations, globally and expectations for India, and how India will engage within the negotiations," he said.

In the meeting with environment minister Bhupendra Yadav on Monday, discussions focused on "key agenda items" such as adap-

tation, technology transfer, climate finance, global stocktake and just transition. This was their first in-person interaction since COP30 in Belém in November last year.

As the nodal authority, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change leads India's participation and engagement on climate change at the multilateral UN forum and other formal and informal platforms. India's participation at the mid-year climate negotiations in Bonn, as well as important informal ministerial meetings such as the Copenhagen Climate Ministerial and the Petersberg Dialogue has been low key.

At the Bonn meeting in June, India participated virtually because of the austerity measures put in place on account of the war in Iran. The virtual participation was supported by a small on-site team comprising technical negotiators and officials from the Indian Embassy in Berlin, Germany.

Even before the austerity measures were announced, India's participation in key annual meetings like the Petersberg Dialogue had been limited. Yadav did not attend the informal ministerial meetings in Copenhagen, Berlin or Brussels, where India was represented by embassy officials. The head-of-delegation meeting in Tokyo was also attended by an embassy official. Indications are that the UNFCCC COP31 High-level Retreat for heads of delegation this week, co-hosted by Azerbaijan and incoming COP31 presidency Türkiye, will see a similar arrangement. These informal meetings discuss key and complex issues to build acceptable compromises.

Govt bonds fall as crude oil climbs above \$90/bbl

Informist
NEW DELHI

Prices of most government bonds ended lower as Brent crude futures for September delivery climbed nearly 2% during the trading session and traded above \$90 per barrel by the end of Indian market hours, dealers said. Short-term bonds outperformed long-term paper as banks' mop-up of Foreign Currency Non-Resident (Bank) deposits so far has been higher than market expectations, driving

demand from asset-liability managers for gilts maturing in under five years, dealers said.

Volatility marked the session as the most-traded gilts swung between gains and losses, closely tracking crude oil prices.

The 10-year benchmark 6.94%, 2036 bond ended at ₹101.02, down from ₹101.14 on Monday. It closed at the day's low after rising as high as ₹100.28 earlier in the session. Its yield rose to 6.7938% on Tuesday from 6.7770% on the previous day.

Publication : The Hindu	Editions : New Delhi
Date :22 July 2026	Page : 16

RECPDCL Signs MoA with Gandhigram Rural Institute for Setting Up 1 MW Solar Power Plant in Tamil Nadu

REC Power Development and Consultancy Limited, a wholly owned subsidiary of REC Limited, has signed a Memorandum of Agreement (MoA) with Gandhigram Rural Institute (GRI), for the establishment of a ground-mounted, grid-connected 1 MW Solar Photovoltaic Power Plant at the institute's campus in Dindigul, Tamil Nadu. The MoA was signed by Mr. Jaspal Singh Kushwaha, General Manager, RECPDCL, and Dr. M. Sundaramari, Registrar, GRI, in the presence of Prof. Dr. N. Panchanatham, Vice-Chancellor, GRI, and Ms. Thara Ramesh, Head of Department & CPM, REC Regional Office, Chennai. Senior officials and representatives from both organizations were also present during the signing ceremony. The proposed 1 MW solar power plant will meet the entire electricity requirement of Gandhigram Rural Institute, enabling the institution to transition to 100% green energy consumption.

Clean energy push is the India's answer to transition challenges: UN climate chief

Jacob Koshy
NEW DELHI

India's main response to the technical and financial challenges of its energy transition lies in decarbonisation and electrification – steps that serve the country's own self-interest and are being backed by both public and private finance, the UN's top climate official said here on Tuesday.

Simon Stiell, Executive Secretary of UN Climate Change, was responding to questions from journalists after two days of talks with Indian Ministers and business leaders. The challenges India faces, he said, run "across a spectrum", from technical hurdles at one end to finance at the other.

On the technical side, Mr. Stiell pointed to (electric) "grids and storage". These were problems, he noted, that most major



Simon Stiell

economies advancing their energy transitions are grappling with. International cooperation could deliver common solutions, he said, adding that grids and storage sit at the heart of the electrification agenda that Türkiye and Australia, holding the COP31 presidency, have made a priority this year. The intermittent nature of solar and wind energy means that relying on coal power, which could be harnessed

night or day, is crucial for India. On the other hand, this also means that the vast amount of solar power available during the day had to be intentionally wasted to keep the electric grid stable. The electrification agenda refers to a plan to ensure at least 35% of the total energy used globally is sourced from electricity, by 2035.

Finance marks the other end of that spectrum. Decarbonisation and electrification fall squarely within India's self-interest, and efforts are under way to mobilise both public and private money to support them, Mr. Stiell said. "India, like many developing countries, struggles in terms of finance for areas such as adaptation... So, the areas of climate finance are key and have been highlighted in our discussions," he added.

Rupee under pressure from rising crude oil prices and strong dollar

Akhil Nallamuthu
bl. research bureau

The rupee remained largely stable over the past week and closed at 96.24 against the dollar on Tuesday. Although the local currency declined about 0.2 per cent during the session, erasing Monday's gains, it largely held its ground amid mixed global cues.

WEEKLY RUPEE VIEW.

Crude oil prices have once again emerged as a key headwind. Brent crude futures, currently trading around \$90 per barrel, have surged nearly 25 per cent in July. The renewed strength follows fresh geopolitical tensions. Risks seem to be elevating after Yemen's Iran-backed Houthis announced plans to impose a naval blockade against Saudi Arabia.

The development has reinforced concerns that disruptions to energy supplies remain a persistent risk, keeping pressure on oil prices and the rupee.

Foreign flows, however, remained supportive. According to NSDL data, net FPI inflows stood at about \$463 million over the past week, taking the cumulative inflows in July to \$3.2 billion.

On the global front, the



dollar continues to remain firm.

While recent US inflation and labour market data have reduced expectations of a rate hike at next week's Federal Reserve meeting, the greenback has continued to draw safe-haven demand amid the renewed geopolitical uncertainty.

Consequently, the dollar index has climbed back towards the 101-mark. More importantly, it sustains above an important level of 100.5 limiting the rupee's ability to benefit from positive foreign inflows.

Overall, the rupee remains caught between supportive capital flows and renewed external headwinds.

WHAT THE CHART SAYS

The rupee remained largely range-bound over the past week. However, it slipped to a nine-week low of 96.53 on Monday before recovering to close at 96.24 on Tuesday. The chart indicates that the

broader trend continues to remain negative.

That said, there is room for a modest recovery from the current level. The rupee can appreciate to 95.8 and, if this resistance is breached, the recovery could extend to 95.4.

However, given the prevailing bearish momentum, a sustained move beyond 95.8 appears unlikely. The price action in the dollar index also supports this view.

The dollar index continues to trade comfortably above the crucial support at 100.5, keeping the broader bias positive.

In the near term, the index is likely to advance towards 101.5 and then 102. Such a move could prevent the rupee from recovering to 95.8 and instead increase the likelihood of a decline towards its record low of 96.96.

On the other hand, if the dollar index corrects towards 100.5, the rupee may recover to 95.8. However, the support at 100.5 is expected to remain firm.

BEARISH OUTLOOK

The rupee may witness a limited recovery in the near term, but the broader bias remains bearish.

A sustained rise in the dollar index could drag the local currency towards its record low of 96.96, while any recovery is likely to face resistance at 95.8.

'20% ethanol blending has not affected food security'

Our Bureau
New Delhi

In the current ethanol supply year (ESY 2025-26), around 3.9 million tonnes (mt) of surplus Food Corporation of India (FCI) rice and roughly 6.8 mt of maize has been used till June for ethanol production.

In a written response to a query in the Rajya Sabha on Monday, Minister of State for Petroleum & Natural Gas Suresh Gopi said, "The target of 20 per cent ethanol blending has not affected food crop availability or India's food security." He said that only surplus foodgrains, as determined by the Depart-

ment of Food & Public Distribution after meeting the requirements of the National Food Security Act, other welfare schemes and maintaining prescribed buffer stocks, are permitted for ethanol production.

WASTE-TO-WEALTH

The programme follows a "waste-to-wealth" approach by utilising surplus agricultural produce, including damaged foodgrains, broken rice and foodgrains unfit for human consumption and other approved feedstocks, which might otherwise remain underutilised or deteriorate in storage, he added.

The average retail price of sugar in the country is cur-



rently in the reasonable range. Only surplus sugar is being diverted for ethanol production. Further, annual increase in retail sugar prices is around 2.5 per cent in comparison to previous sugar season 2024-25, Gopi said. In a separate question in the Rajya Sabha on Monday, he said that during ESY 2023-24 (November 2023-October 2024), the

PSU oil marketing companies (OMCs) procured 679.04 crore litres of ethanol for ₹48,757.01 crore, which rose to 1,033.31 crore litres procured for ₹73,996.48 crore in ESY 2024-25. In ESY 2025-26 (till June), OMCs procured 705.43 crore litres for ₹49,577.36 crore.

He clarified that there is no proposal to mandate the availability of non-blended or lower-blend petrol at select retail outlets. The government's policy is to progressively transition towards cleaner and environmentally-sustainable fuels in accordance with the National Policy on Biofuels and the Ethanol Blended Petrol programme.

**CAPITAL
IDEAS.**



RICHA MISHRA

Remember the "9 PM, 9 Minutes" event on April 5, 2020? It was the ultimate real-time test of India's grid infrastructure, when millions of citizens turned off their home lights simultaneously. What it did was that it created an artificial shockwave that showed exactly why India needs fast, automated energy storage systems.

Before the pandemic, India's energy vulnerability was mostly viewed through the lens of fuel shortages or physical equipment failures. The pandemic changed this by introducing three immediate operational shocks that proved the grid's inability to function smoothly without flexible, fast storage solutions.

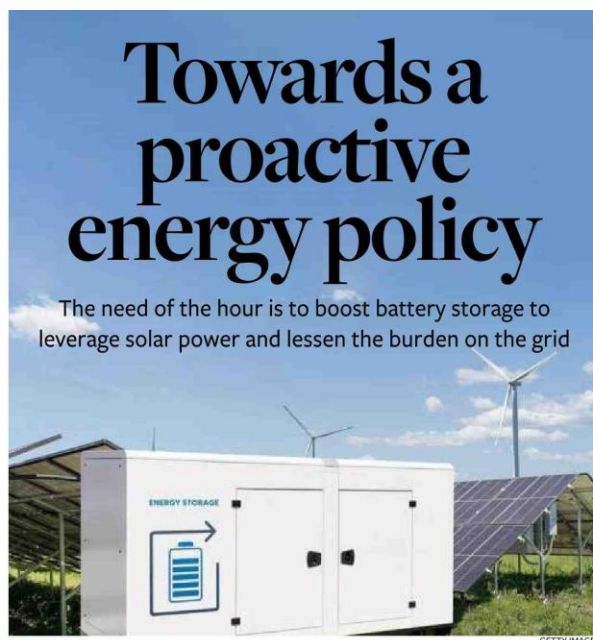
Then came geopolitical conflicts. When geopolitical conflicts disrupt the flow of oil and LNG, the economic and operational impacts on countries including India are immediate and systemic. This chokehold directly triggers a cascading crisis across India's domestic energy infrastructure, exposing its lack of structural shock absorbers.

India relies on imported West Asian LNG to fuel 24,000 MW of gas-fired power infrastructure. A supply halt deactivates these vital peaking plants, which grid operators depend on to manage sharp evening demand spikes. Deprived of gas, utilities must either over-stress ageing coal fleets or enforce rolling blackouts.

The deficit in gas infrastructure shifts the entire burden of real-time frequency stabilisation onto India's overstretched hydroelectric fleet. This operational strain mirrors the vulnerabilities exposed during the pandemic, leaving grid operators with virtually zero technical cushion to absorb unexpected supply-demand imbalances.

INFRASTRUCTURE DEFICIT

This deep infrastructural deficit forces national load dispatch centres to make critical operational compromises. They must either aggressively throttle back variable solar and wind generation — wasting clean energy through forced curtailment — or allow the grid's operational frequency to fluctuate



dangerously, risking localised blackouts and equipment damage from unmanageable frequency swings.

While the government consistently pledges to expand oil, gas, and green energy storage capacities, critics argue that these initiatives are perpetually reactive to external shocks. Instead of proactively building long-term, structural insulation against geopolitical and operational crises, policymakers routinely wait for a market disruption to trigger emergency infrastructure expansions.

A working paper, released in July, by the Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM), 'The Duck and The Camel: Tracing the Net Load on the Indian Power Grid', authored by Sanjeev Sanyal and Satvil Dev, argues that managing demand and price volatility requires storing electricity during times of abundance for release

India's primary energy challenge has shifted from overall generation capacity to optimising the timing and flexibility of power generation

Towards a proactive energy policy

The need of the hour is to boost battery storage to leverage solar power and lessen the burden on the grid

during shortages. The paper demonstrates that India's primary energy challenge has shifted from overall generation capacity to optimising the timing and flexibility of power generation.

It argues that three market signals confirm the diagnosis:

(a) the intra-day price spread between the solar hours and the non-solar hours has widened to a peak-to-trough ratio approaching nine, held back only by the market's price ceiling;

(b) the grid's failures to meet demand rise overwhelmingly in the non-solar hours, relative to solar hours;

(c) solar energy is curtailed in volume because it cannot be used at the moment it is produced. The curtailment figures are striking: the average per day solar curtailment for May 2026 was equivalent to throwing away electricity that could have powered more than a quarter of Delhi for an entire day.

STORING ENERGY

The paper points out that growth in solar, without concomitant and adequate growth in storage and without implementation of other net load smoothening policies, will add to grid stress. This is an argument which has

been making rounds for sometime now, and it is significant that it is now being made by the Economic Advisory Council too.

"The most direct remedy is to store energy when it is abundant and release it when it is scarce, complemented on the demand side by time-of-day tariffs and demand response that move load toward the solar hours," the paper says.

"The gap between need and provision of storage is the greatest, and it is overwhelmingly a battery gap. Grid-scale battery deployment remains well short of the national target, even as pumped hydro has very nearly reached its mark. The recent build-out in storage is significant, but a lot more is still required," it points out.

To drive the energy transition, Indian policymakers have launched a coordinated mix of policy, regulatory, demand-side, and supply-side measures to advance energy storage technologies such as BESS. Key ministries including Power, New & Renewable Energy, and Petroleum & Natural Gas are actively collaborating to expand national storage facilities.

Despite these policy steps, India faces major practical challenges that prevent the rapid deployment of energy storage systems.

The primary obstacle is economic: large-scale battery storage requires massive upfront capital, yet financially distressed Discoms struggle to guarantee timely payments leading to making storage projects independently viable.

Geopolitically, India remains critically dependent on importing fossil fuel as well as foreign battery cells due to a lack of domestic reserves of lithium, cobalt, and nickel. Furthermore, alternative long-duration options such as Pumped Hydro Storage (PHS) suffer from protracted land acquisition and environmental clearance delays.

And finally, the country's harsh, hot climate introduces severe thermal safety risks for lithium batteries, while the regulatory framework still lacks clear, diverse revenue streams to compensate operators for essential grid stabilisation services.

To achieve energy security, India must transition from a reactive crisis-management model to a proactive, structurally insulated strategy. Relying on just-in-time imports of fossil fuels leaves the nation vulnerable to geopolitical shocks, while expanding renewables without storage risks grid failure.

Crude import bill up over 60% in Q1 despite refiners buying less oil

Atul.Mathur@timesofindia.com

New Delhi: India's crude oil import bill shot up more than 60% in the April-June quarter despite refiners buying less oil, highlighting the heavy cost of the disruption in West Asia and the sharp rise in global crude prices.

Provisional data released by the Petroleum Planning and Analysis Cell showed the country spent \$49.8 billion on crude oil imports during the first quarter of the current fiscal, up 61.2% from a year ago. Import volumes, however, fell 4.5% to 59.8 million tonnes, indicating the higher bill was driven almost entirely by costlier crude rather than higher demand. In the corresponding quarter last year, India spent \$32.9 billion to import 62.6 million tonnes of crude.

Analysts estimate that every \$1 increase in crude oil prices raises India's annual import bill by about \$1.5-2 billion. Adding to the pressure is the weakening rupee, which has made dollar-denominated crude im-

ports more expensive.

The impact of elevated prices was visible across the energy basket. LNG imports declined 8.6% in volume during April-June, but the import bill still rose nearly 6% to \$3.6 billion as spot gas prices remained high.

The data showed petroleum product exports fell by a fourth in volume terms to 11.3 million tonnes as refiners prioritised domestic fuel supplies amid global uncertainty. Export earnings, however, rose 40% because of higher international fuel prices.

Online

Headline	HPCL among energy PSUS backing INR 12.5-crore grand butanol challenge for national biofuel innovation		
Publication	AL Circle	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

HPCL among energy PSUS backing INR 12.5-crore grand butanol challenge for national biofuel innovation

<https://www.alcircle.com/press-release/hpcl-among-energy-psus-backing-inr-12-5-crore-grand-butanol-challenge-for-national-biofuel-innovation-120437>

This image has been obtained via official Press Release MC Foundation, India's energy innovation platform, launched the Grand Butanol Challenge in Bengaluru on 17 July a national innovation programme offering up to INR 12.5 crore in prize and grant funding to accelerate indigenous production of bio-butanol.

MC Foundation operates under the aegis of the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG) and is supported by seven of India's largest energy majors Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), GAIL (India) Limited, Oil India Limited, and Petronet LNG Limited.

The Foundation was established to catalyse deep-tech innovation in India's energy and industrial sectors, giving indigenous ventures access to grant funding, pilot deployment and a route to market through the PSUs. For the Challenge, MC+ has partnered with the Centre for Cellular and Molecular Platforms (C-CAMP) as implementation and mentorship partner, tapping into India's wider biotech innovation ecosystem.

The Grand Butanol Challenge combines a prize pool of up to INR 5 crore and a grant pool of up to INR 7.5 crore, inviting applications across three problem statements: fermentation-based production of n-Butanol and Iso-Butanol, catalytic production of the same, and other innovative production pathways.

It targets technologies at Technology Readiness Level (TRL) 47, including microbial production from non-food feedstocks, low-energy separation, bio-derived cetane improvers and field-deployable quality-control hardware. The programme is led by MoPNG, with CHT as technology partner and the Department of Science and Technology (DST) and Department of Biotechnology (DBT) as knowledge partners. Applications close 15 August 2026.

India possesses world-class research infrastructure, exceptional scientific talent and one of the largest energy industries globally. What has been missing is an integrated platform that connects these strengths with startups and entrepreneurs. MC Square Plus has been established to fill that gap by bringing together industry, academia, R&D laboratories and innovators. Our vision is to create a nationwide collaborative ecosystem that accelerates indigenous technologies, enhances energy security and supports India's journey towards a cleaner, more resilient energy future, said Shri Sandeep Maheshwari, Director & CEO, MC Foundation and Executive Director- Corporate Strategy and Business Development at HPCL.

Also speaking at the launch, Dr. Taslimarif Saiyed, Director-CEO, C-CAMP, called biofuels a powerful opportunity at the intersection of biotechnology, sustainability, and energy security, pointing to the promise of next-generation fermentation technologies for the sector.

Delivering the keynote address at the launch, Dr. Madhukar Onkarnath Garg spoke on the evolution of biofuels, the technology and commercialisation challenges facing the sector, and the way forward, drawing on his own work in biofuel production technologies and underlining the strategic importance of biofuels to India's energy security and Net Zero commitments.

Unlock key insights from leading companies and experts across the aluminium ecosystem with our e-Magazine - Mine to Market: ALuminium Producers & Manufacturers 2026

Headline	Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million		
Publication	ANI News	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million

<https://www.aninews.in/news/business/teja-engineering-wins-big-with-multiple-ongc-oampm-orders-worth-837718192-million20260721132029>

Teja Engineering Industries Limited (NSE: TEJA | INE0R1301019), one of India's fast-growing engineering services companies catering to the energy infrastructure sector, has achieved another significant milestone by securing multiple Operation & Maintenance (O&M) contracts from Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). The wins further strengthen the Company's position as a preferred engineering and maintenance partner, backed by a proven execution track record across critical oil & gas infrastructure projects nationwide.

Expanding ONGC Relationship

As part of its growing engagement with ONGC, the Company has secured a 3-year O&M contract through the Government e-Marketplace (GeM) for LP Gas Compression Facilities at Mandapeta and Tatipaka Installations, Rajahmundry Asset, valued at 153.7 million (inclusive of taxes). The contract will be executed for duration of 3 years.

Further strengthening this relationship, the Company has also received a Letter of Award from ONGC Ankleshwar Asset for providing O&M services at GCP-I, GCP-IV and GCS Motwan. The 6-month contract, valued at 28.23 million (inclusive of taxes), further enhances Teja's O&M portfolio within ONGC.

Building a Strong Execution Portfolio

Beyond these contract awards, Teja Engineering continues to expand its project footprint across India's gas infrastructure ecosystem. The Company has successfully executed and is currently undertaking projects for leading energy companies including ONGC, GAIL, Adani, AG&P, BPCL, IOAGPL, Torrent Gas, ATGL, ThinkGas, Gujarat Gas and SGL, demonstrating its capabilities across engineering, commissioning and long-term O&M services.

Commenting on the Order Wins, Mr. Srinivasarao Vakalapudi, Chairman & Managing Director of Teja Engineering Industries Limited, said: "These contract awards reaffirm our commitment to delivering reliable, safe and efficient engineering and operation & maintenance solutions for India's energy sector. They also reflect the confidence our customers place in our technical capabilities, execution excellence and service quality. As energy infrastructure continues to expand across the country, we remain focused on strengthening long-term customer relationships, enhancing operational excellence and creating sustainable value through consistent project execution."

Teja Engineering Industries Limited

Teja Engineering Industries Limited provides Operation & Maintenance (O&M), Erection & Commissioning (E&C), project works, installation, overhauling, decommissioning and recommissioning services for energy infrastructure. The Company supports OEMs, corporates and Public Sector Undertakings (PSUs) across the Oil & Gas, Power and Energy sectors, covering CNG stations, natural gas compression plants, gas distribution terminals and related infrastructure.

With a workforce of 2,900 personnel deployed across client sites, the Company has established a presence across 15 states/UTs in India and manages 728 active O&M sites. Together with the historical track record of the erstwhile proprietorship firm M/s Teja Engineering Services (TES), established in 2002, the Company has completed 397 E&C sites.

The Company also undertakes instrument calibration, non-destructive thickness testing of pressure vessels, and testing and servicing of Safety Relief Valves (SRVs) and Pressure Safety Valves (PSVs). It holds PESO certification for SRV and PSV testing and is certified under ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 for quality, environmental, and occupational health and safety management systems.

For 9M FY26, the company reported Total Income of 54.32 Cr, EBIDTA of 7.07 Cr and Net Profit of 4.00 Crore

Headline	Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million		
Publication	Atulya Hindustan	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million

<https://atulyahindustan.in/teja-engineering-wins-big-with-multiple-ongc-om-orders-worth-%e2%82%b9181-92-million/>

Teja Engineering Industries Limited (NSE: TEJA | INE0R1301019), one of India's fast-growing engineering services companies catering to the energy infrastructure sector, has achieved another significant milestone by securing multiple Operation & Maintenance (O&M) contracts from Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). The wins further strengthen the Company's position as a preferred engineering and maintenance partner, backed by a proven execution track record across critical oil & gas infrastructure projects nationwide.

Expanding ONGC Relationship

As part of its growing engagement with ONGC, the Company has secured a 3-year O&M contract through the Government e-Marketplace (GeM) for LP Gas Compression Facilities at Mandapeta and Tatipaka Installations, Rajahmundry Asset, valued at 153.7 million (inclusive of taxes). The contract will be executed for duration of 3 years.

Further strengthening this relationship, the Company has also received a Letter of Award from ONGC Ankleshwar Asset for providing O&M services at GCP-I, GCP-IV and GCS Motwan. The 6-month contract, valued at 28.23 million (inclusive of taxes), further enhances Teja's O&M portfolio within ONGC.

Building a Strong Execution Portfolio

Beyond these contract awards, Teja Engineering continues to expand its project footprint across India's gas infrastructure ecosystem. The Company has successfully executed and is currently undertaking projects for leading energy companies including ONGC, GAIL, Adani, AG&P, BPCL, IOAGPL, Torrent Gas, ATGL, ThinkGas, Gujarat Gas and SGL, demonstrating its capabilities across engineering, commissioning and long-term O&M services.

Commenting on the Order Wins

Mr. Srinivasarao Vakalapudi, Chairman & Managing Director of

Teja Engineering Industries Limited, said:

These contract awards reaffirm our commitment to delivering reliable, safe and efficient engineering and operation & maintenance solutions for India's energy sector. They also reflect the confidence our customers place in our technical capabilities, execution excellence and service quality. As energy infrastructure continues to expand across the country, we remain focused on strengthening long-term customer relationships, enhancing operational excellence and creating sustainable value through consistent project execution

.Teja Engineering Industries Limited

Teja Engineering Industries Limited provides Operation & Maintenance (O&M), Erection & Commissioning (E&C), project works, installation, overhauling, decommissioning and recommissioning services for energy infrastructure. The Company supports OEMs, corporates and Public Sector Undertakings (PSUs) across the Oil & Gas, Power and Energy sectors, covering CNG stations, natural gas compression plants, gas distribution terminals and related infrastructure.

With a workforce of 2,900 personnel deployed across client sites, the Company has established a presence across 15 states/UTs in India and manages 728 active O&M sites. Together with the historical track record of the erstwhile proprietorship firm M/s Teja Engineering Services (TES), established in 2002, the Company has completed 397 E&C sites.

The Company also undertakes instrument calibration, non-destructive thickness testing of pressure vessels, and testing and servicing of Safety Relief Valves (SRVs) and Pressure Safety Valves (PSVs). It holds PESO certification for SRV and PSV testing and is certified under ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 for quality, environmental, and occupational health and safety management systems.

For 9M FY26, the company reported Total Income of 54.32 Cr, EBIDTA of 7.07 Cr and Net Profit of 4.00 Crore

If you object to the content of this press release, please notify us at pr.error.rectification@gmail.com. We will respond and rectify the situation within 24 hours.

Headline	Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million		
Publication	Birmingham All News Network	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million

<https://www.birminghamallnewsnetwork.com/news/teja-engineering-wins-big-with-multiple-ongc-om-orders-worth-18192-million20260721132012/>

Teja Engineering Industries Limited (NSE: TEJA | INE0R1301019), one of India's fast-growing engineering services companies catering to the energy infrastructure sector, has achieved another significant milestone by securing multiple Operation & Maintenance (O&M) contracts from Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). The wins further strengthen the Company's position as a preferred engineering and maintenance partner, backed by a proven execution track record across critical oil & gas infrastructure projects nationwide.

Expanding ONGC Relationship

As part of its growing engagement with ONGC, the Company has secured a 3-year O&M contract through the Government e-Marketplace (GeM) for LP Gas Compression Facilities at Mandapeta and Tatipaka Installations, Rajahmundry Asset, valued at 153.7 million (inclusive of taxes). The contract will be executed for duration of 3 years.

Further strengthening this relationship, the Company has also received a Letter of Award from ONGC Ankleshwar Asset for providing O&M services at GCP-I, GCP-IV and GCS Motwan. The 6-month contract, valued at 28.23 million (inclusive of taxes), further enhances Teja's O&M portfolio within ONGC.

Building a Strong Execution Portfolio

Beyond these contract awards, Teja Engineering continues to expand its project footprint across India's gas infrastructure ecosystem. The Company has successfully executed and is currently undertaking projects for leading energy companies including ONGC, GAIL, Adani, AG&P, BPCL, IOAGPL, Torrent Gas, ATGL, ThinkGas, Gujarat Gas and SGL, demonstrating its capabilities across engineering, commissioning and long-term O&M services.

Commenting on the Order Wins, Mr. Srinivasarao Vakalapudi, Chairman & Managing Director of Teja Engineering Industries Limited, said: "These contract awards reaffirm our commitment to delivering reliable, safe and efficient engineering and operation & maintenance solutions for India's energy sector. They also reflect the confidence our customers place in our technical capabilities, execution excellence and service quality. As energy infrastructure continues to expand across the country, we remain focused on strengthening long-term customer relationships, enhancing operational excellence and creating sustainable value through consistent project execution."

Teja Engineering Industries Limited

Teja Engineering Industries Limited provides Operation & Maintenance (O&M), Erection & Commissioning (E&C), project works, installation, overhauling, decommissioning and recommissioning services for energy infrastructure. The Company supports OEMs, corporates and Public Sector Undertakings (PSUs) across the Oil & Gas, Power and Energy sectors, covering CNG stations, natural gas compression plants, gas distribution terminals and related infrastructure.

With a workforce of 2,900 personnel deployed across client sites, the Company has established a presence across 15 states/UTs in India and manages 728 active O&M sites. Together with the historical track record of the erstwhile proprietorship firm M/s Teja Engineering Services (TES), established in 2002, the Company has completed 397 E&C sites.

The Company also undertakes instrument calibration, non-destructive thickness testing of pressure vessels, and testing and servicing of Safety Relief Valves (SRVs) and Pressure Safety Valves (PSVs). It holds PESO certification for SRV and PSV testing and is certified under ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 for quality, environmental, and occupational health and safety management systems.

For 9M FY26, the company reported Total Income of 54.32 Cr, EBIDTA of 7.07 Cr and Net Profit of 4.00 Crore

Headline	Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million		
Publication	Buffalo Despatch	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million

<https://www.buffalodespatch.com/news/teja-engineering-wins-big-with-multiple-ongc-om-orders-worth-18192-million20260721132012/>

Teja Engineering Industries Limited (NSE: TEJA | INE0R1301019), one of India's fast-growing engineering services companies catering to the energy infrastructure sector, has achieved another significant milestone by securing multiple Operation & Maintenance (O&M) contracts from Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). The wins further strengthen the Company's position as a preferred engineering and maintenance partner, backed by a proven execution track record across critical oil & gas infrastructure projects nationwide.

Expanding ONGC Relationship

As part of its growing engagement with ONGC, the Company has secured a 3-year O&M contract through the Government e-Marketplace (GeM) for LP Gas Compression Facilities at Mandapeta and Tatipaka Installations, Rajahmundry Asset, valued at 153.7 million (inclusive of taxes). The contract will be executed for duration of 3 years.

Further strengthening this relationship, the Company has also received a Letter of Award from ONGC Ankleshwar Asset for providing O&M services at GCP-I, GCP-IV and GCS Motwan. The 6-month contract, valued at 28.23 million (inclusive of taxes), further enhances Teja's O&M portfolio within ONGC.

Building a Strong Execution Portfolio

Beyond these contract awards, Teja Engineering continues to expand its project footprint across India's gas infrastructure ecosystem. The Company has successfully executed and is currently undertaking projects for leading energy companies including ONGC, GAIL, Adani, AG&P, BPCL, IOAGPL, Torrent Gas, ATGL, ThinkGas, Gujarat Gas and SGL, demonstrating its capabilities across engineering, commissioning and long-term O&M services.

Commenting on the Order Wins, Mr. Srinivasarao Vakalapudi, Chairman & Managing Director of Teja Engineering Industries Limited, said: "These contract awards reaffirm our commitment to delivering reliable, safe and efficient engineering and operation & maintenance solutions for India's energy sector. They also reflect the confidence our customers place in our technical capabilities, execution excellence and service quality. As energy infrastructure continues to expand across the country, we remain focused on strengthening long-term customer relationships, enhancing operational excellence and creating sustainable value through consistent project execution."

Teja Engineering Industries Limited

Teja Engineering Industries Limited provides Operation & Maintenance (O&M), Erection & Commissioning (E&C), project works, installation, overhauling, decommissioning and recommissioning services for energy infrastructure. The Company supports OEMs, corporates and Public Sector Undertakings (PSUs) across the Oil & Gas, Power and Energy sectors, covering CNG stations, natural gas compression plants, gas distribution terminals and related infrastructure.

With a workforce of 2,900 personnel deployed across client sites, the Company has established a presence across 15 states/UTs in India and manages 728 active O&M sites. Together with the historical track record of the erstwhile proprietorship firm M/s Teja Engineering Services (TES), established in 2002, the Company has completed 397 E&C sites.

The Company also undertakes instrument calibration, non-destructive thickness testing of pressure vessels, and testing and servicing of Safety Relief Valves (SRVs) and Pressure Safety Valves (PSVs). It holds PESO certification for SRV and PSV testing and is certified under ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 for quality, environmental, and occupational health and safety management systems.

For 9M FY26, the company reported Total Income of 54.32 Cr, EBIDTA of 7.07 Cr and Net Profit of 4.00 Crore

Headline	Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million		
Publication	Chhattisgarh Today	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million

<https://www.chhattisgarhtoday.in/news/teja-engineering-wins-big-with-multiple-ongc-om-orders-worth-18192-million20260721132012/>

Teja Engineering Industries Limited (NSE: TEJA | INE0R1301019), one of India's fast-growing engineering services companies catering to the energy infrastructure sector, has achieved another significant milestone by securing multiple Operation & Maintenance (O&M) contracts from Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). The wins further strengthen the Company's position as a preferred engineering and maintenance partner, backed by a proven execution track record across critical oil & gas infrastructure projects nationwide.

Expanding ONGC Relationship

As part of its growing engagement with ONGC, the Company has secured a 3-year O&M contract through the Government e-Marketplace (GeM) for LP Gas Compression Facilities at Mandapeta and Tatipaka Installations, Rajahmundry Asset, valued at 153.7 million (inclusive of taxes). The contract will be executed for duration of 3 years.

Further strengthening this relationship, the Company has also received a Letter of Award from ONGC Ankleshwar Asset for providing O&M services at GCP-I, GCP-IV and GCS Motwan. The 6-month contract, valued at 28.23 million (inclusive of taxes), further enhances Teja's O&M portfolio within ONGC.

Building a Strong Execution Portfolio

Beyond these contract awards, Teja Engineering continues to expand its project footprint across India's gas infrastructure ecosystem. The Company has successfully executed and is currently undertaking projects for leading energy companies including ONGC, GAIL, Adani, AG&P, BPCL, IOAGPL, Torrent Gas, ATGL, ThinkGas, Gujarat Gas and SGL, demonstrating its capabilities across engineering, commissioning and long-term O&M services.

Commenting on the Order Wins, Mr. Srinivasarao Vakalapudi, Chairman & Managing Director of Teja Engineering Industries Limited, said: "These contract awards reaffirm our commitment to delivering reliable, safe and efficient engineering and operation & maintenance solutions for India's energy sector. They also reflect the confidence our customers place in our technical capabilities, execution excellence and service quality. As energy infrastructure continues to expand across the country, we remain focused on strengthening long-term customer relationships, enhancing operational excellence and creating sustainable value through consistent project execution."

Teja Engineering Industries Limited

Teja Engineering Industries Limited provides Operation & Maintenance (O&M), Erection & Commissioning (E&C), project works, installation, overhauling, decommissioning and recommissioning services for energy infrastructure. The Company supports OEMs, corporates and Public Sector Undertakings (PSUs) across the Oil & Gas, Power and Energy sectors, covering CNG stations, natural gas compression plants, gas distribution terminals and related infrastructure.

With a workforce of 2,900 personnel deployed across client sites, the Company has established a presence across 15 states/UTs in India and manages 728 active O&M sites. Together with the historical track record of the erstwhile proprietorship firm M/s Teja Engineering Services (TES), established in 2002, the Company has completed 397 E&C sites.

The Company also undertakes instrument calibration, non-destructive thickness testing of pressure vessels, and testing and servicing of Safety Relief Valves (SRVs) and Pressure Safety Valves (PSVs). It holds PESO certification for SRV and PSV testing and is certified under ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 for quality, environmental, and occupational health and safety management systems.

For 9M FY26, the company reported Total Income of 54.32 Cr, EBIDTA of 7.07 Cr and Net Profit of 4.00 Crore

Headline	Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million		
Publication	Delhi Live News	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million

<https://www.delhilivenews.in/news/teja-engineering-wins-big-with-multiple-ongc-om-orders-worth-18192-million20260721132012/>

Teja Engineering Industries Limited (NSE: TEJA | INE0R1301019), one of India's fast-growing engineering services companies catering to the energy infrastructure sector, has achieved another significant milestone by securing multiple Operation & Maintenance (O&M) contracts from Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). The wins further strengthen the Company's position as a preferred engineering and maintenance partner, backed by a proven execution track record across critical oil & gas infrastructure projects nationwide.

Expanding ONGC Relationship

As part of its growing engagement with ONGC, the Company has secured a 3-year O&M contract through the Government e-Marketplace (GeM) for LP Gas Compression Facilities at Mandapeta and Tatipaka Installations, Rajahmundry Asset, valued at 153.7 million (inclusive of taxes). The contract will be executed for duration of 3 years.

Further strengthening this relationship, the Company has also received a Letter of Award from ONGC Ankleshwar Asset for providing O&M services at GCP-I, GCP-IV and GCS Motwan. The 6-month contract, valued at 28.23 million (inclusive of taxes), further enhances Teja's O&M portfolio within ONGC.

Building a Strong Execution Portfolio

Beyond these contract awards, Teja Engineering continues to expand its project footprint across India's gas infrastructure ecosystem. The Company has successfully executed and is currently undertaking projects for leading energy companies including ONGC, GAIL, Adani, AG&P, BPCL, IOAGPL, Torrent Gas, ATGL, ThinkGas, Gujarat Gas and SGL, demonstrating its capabilities across engineering, commissioning and long-term O&M services.

Commenting on the Order Wins, Mr. Srinivasarao Vakalapudi, Chairman & Managing Director of Teja Engineering Industries Limited, said: "These contract awards reaffirm our commitment to delivering reliable, safe and efficient engineering and operation & maintenance solutions for India's energy sector. They also reflect the confidence our customers place in our technical capabilities, execution excellence and service quality. As energy infrastructure continues to expand across the country, we remain focused on strengthening long-term customer relationships, enhancing operational excellence and creating sustainable value through consistent project execution."

Teja Engineering Industries Limited

Teja Engineering Industries Limited provides Operation & Maintenance (O&M), Erection & Commissioning (E&C), project works, installation, overhauling, decommissioning and recommissioning services for energy infrastructure. The Company supports OEMs, corporates and Public Sector Undertakings (PSUs) across the Oil & Gas, Power and Energy sectors, covering CNG stations, natural gas compression plants, gas distribution terminals and related infrastructure.

With a workforce of 2,900 personnel deployed across client sites, the Company has established a presence across 15 states/UTs in India and manages 728 active O&M sites. Together with the historical track record of the erstwhile proprietorship firm M/s Teja Engineering Services (TES), established in 2002, the Company has completed 397 E&C sites.

The Company also undertakes instrument calibration, non-destructive thickness testing of pressure vessels, and testing and servicing of Safety Relief Valves (SRVs) and Pressure Safety Valves (PSVs). It holds PESO certification for SRV and PSV testing and is certified under ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 for quality, environmental, and occupational health and safety management systems.

For 9M FY26, the company reported Total Income of 54.32 Cr, EBIDTA of 7.07 Cr and Net Profit of 4.00 Crore

Headline	LNG consumption declines 6.5% on costly import, lower output		
Publication	ET Energyworld	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

LNG consumption declines 6.5% on costly import, lower output

<https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/lng-consumption-declines-6-5on-costly-import-lower-output/132527018>

India's domestic natural gas production has been declining for the past two years, mainly because of falling output from Reliance Industries' KG basin fields.

In the April-June quarter, production from private-sector fields fell 7.5 per cent, while output from state-run producers declined 2 per cent. A surge in global LNG prices due to the Iran war, coupled with declining domestic output, is dragging down India's natural gas consumption

Gas consumption fell 6.5 per cent year-on-year in the April-June quarter to 16 billion cubic meters (bcm), according to oil ministry data. Domestic output declined 4.3 per cent to 8.3 bcm as production from Reliance Industries ' and ONGC 's fields fell, while LNG imports dropped 8.6 per cent to 7.7 bcm as soaring spot prices made imports unaffordable for some customers.

Advt India depends on imports for half of its gas consumption, with the majority of LNG supplies coming from Gulf countries. The war disrupted those supplies, increasing reliance on cargoes from elsewhere. Most LNG is procured under long-term contracts, with only a small share sourced from the spot market.

The war cut off supplies from Qatar, India's largest LNG supplier under a long-term contract, forcing Indian buyers to seek more expensive alternatives. Dependence on spot purchases has risen even as prices have skyrocketed.

Global LNG prices surged after the Iran war began on February 28. JKM, the Asian spot LNG benchmark, averaged \$20 per mmbtu in March, nearly double February's \$10.7. The benchmark averaged \$16.9 in April, \$18.3 in May and \$16 in June. A recent resumption of US-Iran hostilities has again pushed the benchmark above \$20 per mmbtu.

Show More Most of India's long-term LNG contracts are linked to crude prices, while a major long-term contract with the US is benchmarked to US Henry Hub gas prices. Henry Hub prices were far less volatile than regional LNG benchmarks, making US supplies more attractive to Indian buyers during the current crisis. In normal times, however, US LNG is often uneconomical for Indian consumers because of high shipping costs.

India's domestic natural gas production has been declining for the past two years, mainly because of falling output from Reliance Industries ' KG basin fields. In the April-June quarter, production from private-sector fields fell 7.5 per cent, while output from state-run producers declined 2 per cent. The private sector accounts for 37 per cent of India's domestic natural gas production.

Headline	Teja Engineering secures ₹18.2 crore contracts from ONGC		
Publication	ET Energyworld	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Teja Engineering secures ₹18.2 crore contracts from ONGC

<https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/teja-engineering-lands-182-crore-om-contracts-with-ongc/132535825>

The engineering services provider won operation and maintenance orders across ONGC's Rajahmundry and Ankleshwar assets.

The company said it is executing projects for several energy firms, including ONGC, GAIL, Adani, BPCL and Gujarat Gas, covering engineering, commissioning and long-term operation and maintenance services.

Teja Engineering Industries , an engineering services provider for the energy sectors , on Tuesday said it has secured multiple operation and maintenance (O&M) contracts from Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) with a combined value of about 18.19 crore.

According to a regulatory filing, the company has won a three-year contract, awarded through the Government e-Marketplace for LP Gas Compression Facilities at the Mandapeta and Tatipaka installations under ONGC's Rajahmundry Asset . The contract is valued at 15.36 crore.

Advt Teja Engineering has also received a Letter of Award from ONGC's Ankleshwar Asset for providing O&M services at GCP-I, GCP-IV and GCS Motwan. The six-month contract is valued at 2.82 crore.

As energy infrastructure continues to expand across the country, we remain focused on strengthening long-term customer relationships, enhancing operational excellence and creating sustainable value through consistent project execution , said Srinivasarao Vakalapudi, Chairman and Managing Director, Teja Engineering Industries.

The company said it is currently executing projects for several energy companies, including ONGC, GAIL, Adani, AG&P, BPCL, IOAGPL, Torrent Gas, ATGL, ThinkGas, Gujarat Gas and SGL, spanning engineering, commissioning and long-term operation and maintenance services.

Headline	LNG consumption declines 6.5% on costly import, lower output		
Publication	ET Government	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

LNG consumption declines 6.5% on costly import, lower output

<https://government.economictimes.indiatimes.com/news/economy/lng-consumption-declines-6-5-on-costly-import-lower-output/132529008>

Gas consumption fell 6.5 per cent year-on-year in the April-June quarter to 16 billion cubic meters (bcm), according to oil ministry data.

A surge in global LNG prices due to the Iran war, coupled with declining domestic output, is dragging down India's natural gas consumption

Gas consumption fell 6.5 per cent year-on-year in the April-June quarter to 16 billion cubic meters (bcm), according to oil ministry data. Domestic output declined 4.3 per cent to 8.3 bcm as production from Reliance Industries ' and ONGC 's fields fell, while LNG imports dropped 8.6 per cent to 7.7 bcm as soaring spot prices made imports unaffordable for some customers.

India depends on imports for half of its gas consumption, with the majority of LNG supplies coming from Gulf countries. The war disrupted those supplies, increasing reliance on cargoes from elsewhere. Most LNG is procured under long-term contracts, with only a small share sourced from the spot market.

The war cut off supplies from Qatar, India's largest LNG supplier under a long-term contract, forcing Indian buyers to seek more expensive alternatives. Dependence on spot purchases has risen even as prices have skyrocketed.

Global LNG prices surged after the Iran war began on February 28. JKM, the Asian spot LNG benchmark, averaged \$20 per mmbtu in March, nearly double February's \$10.7. The benchmark averaged \$16.9 in April, \$18.3 in May and \$16 in June. A recent resumption of US-Iran hostilities has again pushed the benchmark above \$20 per mmbtu.

Most of India's long-term LNG contracts are linked to crude prices, while a major long-term contract with the US is benchmarked to US Henry Hub gas prices. Henry Hub prices were far less volatile than regional LNG benchmarks, making US supplies more attractive to Indian buyers during the current crisis. In normal times, however, US LNG is often uneconomical for Indian consumers because of high shipping costs.

India's domestic natural gas production has been declining for the past two years, mainly because of falling output from Reliance Industries ' KG basin fields. In the April-June quarter, production from private-sector fields fell 7.5 per cent, while output from state-run producers declined 2 per cent. The private sector accounts for 37 per cent of India's domestic natural gas production.

Headline	Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million		
Publication	England News Portal	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million

<https://www.englishnewsportal.com/news/teja-engineering-wins-big-with-multiple-ongc-om-orders-worth-18192-million20260721132012/>

Teja Engineering Industries Limited (NSE: TEJA | INE0R1301019), one of India's fast-growing engineering services companies catering to the energy infrastructure sector, has achieved another significant milestone by securing multiple Operation & Maintenance (O&M) contracts from Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). The wins further strengthen the Company's position as a preferred engineering and maintenance partner, backed by a proven execution track record across critical oil & gas infrastructure projects nationwide.

Expanding ONGC Relationship

As part of its growing engagement with ONGC, the Company has secured a 3-year O&M contract through the Government e-Marketplace (GeM) for LP Gas Compression Facilities at Mandapeta and Tatipaka Installations, Rajahmundry Asset, valued at 153.7 million (inclusive of taxes). The contract will be executed for duration of 3 years.

Further strengthening this relationship, the Company has also received a Letter of Award from ONGC Ankleshwar Asset for providing O&M services at GCP-I, GCP-IV and GCS Motwan. The 6-month contract, valued at 28.23 million (inclusive of taxes), further enhances Teja's O&M portfolio within ONGC.

Building a Strong Execution Portfolio

Beyond these contract awards, Teja Engineering continues to expand its project footprint across India's gas infrastructure ecosystem. The Company has successfully executed and is currently undertaking projects for leading energy companies including ONGC, GAIL, Adani, AG&P, BPCL, IOAGPL, Torrent Gas, ATGL, ThinkGas, Gujarat Gas and SGL, demonstrating its capabilities across engineering, commissioning and long-term O&M services.

Commenting on the Order Wins, Mr. Srinivasarao Vakalapudi, Chairman & Managing Director of Teja Engineering Industries Limited, said: "These contract awards reaffirm our commitment to delivering reliable, safe and efficient engineering and operation & maintenance solutions for India's energy sector. They also reflect the confidence our customers place in our technical capabilities, execution excellence and service quality. As energy infrastructure continues to expand across the country, we remain focused on strengthening long-term customer relationships, enhancing operational excellence and creating sustainable value through consistent project execution."

Teja Engineering Industries Limited

Teja Engineering Industries Limited provides Operation & Maintenance (O&M), Erection & Commissioning (E&C), project works, installation, overhauling, decommissioning and recommissioning services for energy infrastructure. The Company supports OEMs, corporates and Public Sector Undertakings (PSUs) across the Oil & Gas, Power and Energy sectors, covering CNG stations, natural gas compression plants, gas distribution terminals and related infrastructure.

With a workforce of 2,900 personnel deployed across client sites, the Company has established a presence across 15 states/UTs in India and manages 728 active O&M sites. Together with the historical track record of the erstwhile proprietorship firm M/s Teja Engineering Services (TES), established in 2002, the Company has completed 397 E&C sites.

The Company also undertakes instrument calibration, non-destructive thickness testing of pressure vessels, and testing and servicing of Safety Relief Valves (SRVs) and Pressure Safety Valves (PSVs). It holds PESO certification for SRV and PSV testing and is certified under ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 for quality, environmental, and occupational health and safety management systems.

For 9M FY26, the company reported Total Income of 54.32 Cr, EBIDTA of 7.07 Cr and Net Profit of 4.00 Crore

Headline	ONGC Unveils Urja Bharat Convention Centre, Expands Into India's MICE Industry		
Publication	Everything Experiential	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

ONGC Unveils Urja Bharat Convention Centre, Expands Into India's MICE Industry

<https://everythingexperiential.com/article/ongc-unveils-urja-bharat-convention-centre-expands-into-india-s-mice-industry-615786>

Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) has formally entered India's Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) sector with the launch of the Urja Bharat Convention Centre (UBCC) at its 250-acre Advanced Training Institute (ATI) campus in Canaguinim, Goa. The convention centre was unveiled during the inaugural edition of Urjatva, a two-day industry engagement programme that brought together leaders from the convention, exhibition, tourism, hospitality and experiential events sectors to explore Goa's future as a business events destination.

Developed within a record 13 months, the Urja Bharat Convention Centre has been envisioned as a fully integrated ecosystem capable of hosting conferences, exhibitions, corporate conventions, government summits, trade fairs, destination weddings, cultural programmes, live entertainment and executive learning programmes. During the event, ONGC also unveiled the Urja Bharat Convention Centre's brand identity, inspired by shades of yellow and orange and drawing inspiration from Goa's laterite stone architecture.

The convention campus comprises the Prithvi Grand Convention Centre, the Vayu Exhibition Hall and the Akash Management Development Facility. The Prithvi Grand Convention Centre can accommodate nearly 4,000 delegates and is equipped with a 30-metre Direct View LED videowall, concert-grade line array sound system, AV-over-IP architecture, PTZ broadcast cameras and simultaneous interpretation facilities in up to eight languages. The Vayu Exhibition Hall offers approximately 7,200 square metres of pillar-less, air-conditioned exhibition space, while the Akash Management Development Facility features premium boardrooms, hybrid conferencing facilities, wireless presentation technology, digital nameplates and multilingual interpretation capabilities.

The campus also includes Sagar Setu, a waterfront venue designed for destination weddings, gala dinners, networking evenings and experiential events. Additional infrastructure includes executive accommodation, smart building management systems, integrated surveillance, high-speed connectivity and advanced event technology.

Sustainability has been integrated into the development of the venue. ATI Goa houses one of India's largest behind-the-meter microgrid systems, featuring a 10 MW Battery Energy Storage System (BESS), rooftop and ground-mounted solar installations and a vertical-axis wind generator. According to ONGC, the long-term goal is to power events hosted at the venue primarily through clean energy.

Commenting on the initiative, Saket Gupta, Executive Director, ONGC and Chief of ATI Goa, said, "We have organised Urjatva as a platform where MICE industry experts and leaders can experience the venue firsthand and share their inputs on how we can take this venue to the level it truly deserves. Together, Prithvi, Vayu and Akash create a comprehensive MICE ecosystem capable of hosting events of varying scales and formats."

The two-day Urjatva programme featured campus tours, networking sessions, panel discussions and an interactive feedback session aimed at shaping the convention centre's future roadmap. Representatives from Goa Tourism, the India Convention Promotion Bureau (ICPB), the Indian Exhibition Industry Association (IEIA), international convention bodies, event organisers, exhibition companies, hospitality brands and venue operators participated in the event. Discussions focused on Goa's convention potential, destination marketing, connectivity, convention bidding initiatives, AI-enabled event technologies, sustainability, workforce development and ease of doing business.

The launch of the Urja Bharat Convention Centre marks ONGC's entry into the country's growing MICE sector, adding a new convention and exhibition destination to Goa's business events infrastructure.

Headline	Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million		
Publication	France Net Work Times	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million

<https://www.francenetworktimes.com/news/teja-engineering-wins-big-with-multiple-ongc-om-orders-worth-18192-million20260721132012/>

Teja Engineering Industries Limited (NSE: TEJA | INE0R1301019), one of India's fast-growing engineering services companies catering to the energy infrastructure sector, has achieved another significant milestone by securing multiple Operation & Maintenance (O&M) contracts from Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). The wins further strengthen the Company's position as a preferred engineering and maintenance partner, backed by a proven execution track record across critical oil & gas infrastructure projects nationwide.

Expanding ONGC Relationship

As part of its growing engagement with ONGC, the Company has secured a 3-year O&M contract through the Government e-Marketplace (GeM) for LP Gas Compression Facilities at Mandapeta and Tatipaka Installations, Rajahmundry Asset, valued at 153.7 million (inclusive of taxes). The contract will be executed for duration of 3 years.

Further strengthening this relationship, the Company has also received a Letter of Award from ONGC Ankleshwar Asset for providing O&M services at GCP-I, GCP-IV and GCS Motwan. The 6-month contract, valued at 28.23 million (inclusive of taxes), further enhances Teja's O&M portfolio within ONGC.

Building a Strong Execution Portfolio

Beyond these contract awards, Teja Engineering continues to expand its project footprint across India's gas infrastructure ecosystem. The Company has successfully executed and is currently undertaking projects for leading energy companies including ONGC, GAIL, Adani, AG&P, BPCL, IOAGPL, Torrent Gas, ATGL, ThinkGas, Gujarat Gas and SGL, demonstrating its capabilities across engineering, commissioning and long-term O&M services.

Commenting on the Order Wins, Mr. Srinivasarao Vakalapudi, Chairman & Managing Director of Teja Engineering Industries Limited, said: "These contract awards reaffirm our commitment to delivering reliable, safe and efficient engineering and operation & maintenance solutions for India's energy sector. They also reflect the confidence our customers place in our technical capabilities, execution excellence and service quality. As energy infrastructure continues to expand across the country, we remain focused on strengthening long-term customer relationships, enhancing operational excellence and creating sustainable value through consistent project execution."

Teja Engineering Industries Limited

Teja Engineering Industries Limited provides Operation & Maintenance (O&M), Erection & Commissioning (E&C), project works, installation, overhauling, decommissioning and recommissioning services for energy infrastructure. The Company supports OEMs, corporates and Public Sector Undertakings (PSUs) across the Oil & Gas, Power and Energy sectors, covering CNG stations, natural gas compression plants, gas distribution terminals and related infrastructure.

With a workforce of 2,900 personnel deployed across client sites, the Company has established a presence across 15 states/UTs in India and manages 728 active O&M sites. Together with the historical track record of the erstwhile proprietorship firm M/s Teja Engineering Services (TES), established in 2002, the Company has completed 397 E&C sites.

The Company also undertakes instrument calibration, non-destructive thickness testing of pressure vessels, and testing and servicing of Safety Relief Valves (SRVs) and Pressure Safety Valves (PSVs). It holds PESO certification for SRV and PSV testing and is certified under ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 for quality, environmental, and occupational health and safety management systems.

For 9M FY26, the company reported Total Income of 54.32 Cr, EBIDTA of 7.07 Cr and Net Profit of 4.00 Crore

Headline	Oil and Natural Gas Corporation shares gain 2.01% in early trade		
Publication	MSN India	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Oil and Natural Gas Corporation shares gain 2.01% in early trade

<https://www.msn.com/en-in/foodanddrink/foodnews/oil-and-natural-gas-corporation-shares-gain-2-01-in-early-trade/ar-AA28h83u>

Alpha Desk Oil and Natural Gas Corporation shares rose by 2.01% to Rs 252.26 at 9:29 am on Monday. The stock is a constituent of the Nifty 50 index.

Financial Performance Review (Consolidated)

For the quarter-ending March 2026, Oil and Natural Gas Corporation reported a consolidated revenue of Rs 173,805.19 Crore. This marks an increase of 3.81% from Rs 167,422.93 Crore reported in the December 2025 quarter. The net profit for the March 2026 quarter was Rs 10,884.95 Crore, which is a decrease of 8.14% from Rs 11,849.18 Crore in the previous quarter. Earnings Per Share (EPS) for the same period was Rs 8.60, a rise of 8.04% from Rs 7.96 in December 2025.

Annually, the company's consolidated revenue for the year ending March 2026 was Rs 662,247.32 Crore, reflecting an 8.19% increase from Rs 612,065.37 Crore in the year ending March 2025. Consolidated net profit reached Rs 46,791.19 Crore for the year ending March 2026, marking a significant increase of 25.47% from Rs 37,293.02 Crore in the previous fiscal year. The annual EPS for March 2026 was Rs 32.93, compared to Rs 28.80 in March 2025, showing a growth of 14.34%.

From the cash flow statement, cash flow from operating activities increased by 23.01% to Rs 112,719 Crore in the year ending March 2026 from Rs 90,868 Crore in the year ending March 2025. Investing activities showed an outflow of Rs 57,675 Crore in the year ending March 2026, a 34.06% increase from Rs 43,021 Crore in the year ending March 2025. Financing activities resulted in an outflow of Rs 56,330 Crore in the year ending March 2026, an increase of 17.58% compared to Rs 47,907 Crore in the year ending March 2025. The net cash flow decreased to an outflow of Rs 1,030 Crore in the year ending March 2026 from an inflow of Rs 59 Crore in the year ending March 2025.

On the balance sheet, the total liabilities of Oil and Natural Gas Corporation increased to Rs 791,905 Crore in the year ending March 2026, a 4.37% rise from Rs 758,723 Crore in the year ending March 2025. Fixed assets grew by 1.99% to Rs 448,523 Crore in the year ending March 2026 from Rs 439,771 Crore in the year ending March 2025. Reserves & Surplus increased by 8.40% to Rs 365,477 Crore in the year ending March 2026 compared to Rs 337,150 Crore in the year ending March 2025.

Corporate Actions & Key Announcements

Recent announcements from Oil and Natural Gas Corporation include an update under Regulation 30 (LODR) regarding a press release/media release on July 17, 2026, concerning the completion of two deep geothermal wells at Puga by the Hon'ble Lieutenant Governor of Ladakh. Additionally, a revision in Credit Rating was announced on July 16, 2026, and a change in Senior Management was reported on July 01, 2026.

The company has consistently rewarded shareholders through dividends. The most recent dividend declared was an Interim Dividend of Rs 6.25 per share (125%) on February 6, 2026, with an ex-date of February 18, 2026. Prior to that, an Interim Dividend of Rs 6.00 per share (120%) was announced on October 31, 2025, with an ex-date of November 14, 2025.

The company has also had bonus issues in the past, with a 1:2 bonus ratio announced on October 27, 2016, with an ex-date of December 15, 2016. Stock splits have also occurred, with the last split from Rs 10 to Rs 5 face value taking effect on February 8, 2011, with an ex-date of February 8, 2011.

Oil and Natural Gas Corporation's shares gained 2.01% to Rs 252.26, reflecting investor reaction to the market dynamics and the company's financial standing and corporate developments. As of July 20, 2026, the sentiment surrounding the stock is neutral.

Headline	ONGC Unveils Urja Bharat Convention Centre in Goa as Premier MICE Destination		
Publication	PSU India	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

ONGC Unveils Urja Bharat Convention Centre in Goa as Premier MICE Destination

<https://www.psuindia.com/psu-news/ongc-unveils-urja-bharat-convention-centre-in-go-a-as-premier-mice-destination-552723>

State-run energy major Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) has officially launched the Urja Bharat Convention Centre (UBCC) at its Advanced Training Institute in Betul, Goa.

BETUL, GOA State-run energy major Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) has officially launched the Urja Bharat Convention Centre (UBCC) at its Advanced Training Institute in Betul, Goa.

The premier venue was showcased during a two-day event on July 18/19, 2026, drawing over 100 industry leaders, corporate decision-makers, and top MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) event managers from across the country.

World-Class Infrastructure & Venue Capabilities

Situated between the Arabian Sea and coastal greenery, UBCC offers expansive, state-of-the-art facilities designed for global summits, trade expos, and large-scale corporate events:

Prithvi (Convention Hall): A flagship convention space capable of hosting over 3,500+ delegates.

Vayu (Exhibition Hall): A massive 7,200 sq. m. column-free exhibition facility tailored for major trade fairs and industrial expos.

Akash (Academic & Conference Hub): Spanning 8,353 sq. m. of built-up area, this zone houses a 150-seat auditorium, 8 syndicate rooms, 8 classrooms, and specialized conference setups.

MICE Sector Impact: By blending high-capacity modern infrastructure with Goa's tourism appeal, ONGC aims to establish UBCC as a central hub for national and international business gatherings.

Headline	Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million		
Publication	Telangana Journal	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Teja Engineering Wins Big with Multiple ONGC O&M Orders Worth ₹181.92 Million

<https://www.telanganajournal.in/news/teja-engineering-wins-big-with-multiple-ongc-om-orders-worth-18192-million20260721132012/>

Teja Engineering Industries Limited (NSE: TEJA | INE0R1301019), one of India's fast-growing engineering services companies catering to the energy infrastructure sector, has achieved another significant milestone by securing multiple Operation & Maintenance (O&M) contracts from Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). The wins further strengthen the Company's position as a preferred engineering and maintenance partner, backed by a proven execution track record across critical oil & gas infrastructure projects nationwide.

Expanding ONGC Relationship

As part of its growing engagement with ONGC, the Company has secured a 3-year O&M contract through the Government e-Marketplace (GeM) for LP Gas Compression Facilities at Mandapeta and Tatipaka Installations, Rajahmundry Asset, valued at 153.7 million (inclusive of taxes). The contract will be executed for duration of 3 years.

Further strengthening this relationship, the Company has also received a Letter of Award from ONGC Ankleshwar Asset for providing O&M services at GCP-I, GCP-IV and GCS Motwan. The 6-month contract, valued at 28.23 million (inclusive of taxes), further enhances Teja's O&M portfolio within ONGC.

Building a Strong Execution Portfolio

Beyond these contract awards, Teja Engineering continues to expand its project footprint across India's gas infrastructure ecosystem. The Company has successfully executed and is currently undertaking projects for leading energy companies including ONGC, GAIL, Adani, AG&P, BPCL, IOAGPL, Torrent Gas, ATGL, ThinkGas, Gujarat Gas and SGL, demonstrating its capabilities across engineering, commissioning and long-term O&M services.

Commenting on the Order Wins, Mr. Srinivasarao Vakalapudi, Chairman & Managing Director of Teja Engineering Industries Limited, said: "These contract awards reaffirm our commitment to delivering reliable, safe and efficient engineering and operation & maintenance solutions for India's energy sector. They also reflect the confidence our customers place in our technical capabilities, execution excellence and service quality. As energy infrastructure continues to expand across the country, we remain focused on strengthening long-term customer relationships, enhancing operational excellence and creating sustainable value through consistent project execution."

Teja Engineering Industries Limited

Teja Engineering Industries Limited provides Operation & Maintenance (O&M), Erection & Commissioning (E&C), project works, installation, overhauling, decommissioning and recommissioning services for energy infrastructure. The Company supports OEMs, corporates and Public Sector Undertakings (PSUs) across the Oil & Gas, Power and Energy sectors, covering CNG stations, natural gas compression plants, gas distribution terminals and related infrastructure.

With a workforce of 2,900 personnel deployed across client sites, the Company has established a presence across 15 states/UTs in India and manages 728 active O&M sites. Together with the historical track record of the erstwhile proprietorship firm M/s Teja Engineering Services (TES), established in 2002, the Company has completed 397 E&C sites.

The Company also undertakes instrument calibration, non-destructive thickness testing of pressure vessels, and testing and servicing of Safety Relief Valves (SRVs) and Pressure Safety Valves (PSVs). It holds PESO certification for SRV and PSV testing and is certified under ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 for quality, environmental, and occupational health and safety management systems.

Headline	Teja Engineering wins ₹18-crore O&M orders from ONGC		
Publication	The Hindu Business Line	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Teja Engineering wins ₹18-crore O&M orders from ONGC

<https://www.thehindubusinessline.com/companies/teja-engineering-wins-18-crore-om-orders-from-ongc/article71248571.ece>

The company is currently undertaking projects for ONGC, GAIL, Adani, AG&P, BPCL, IOAGPL, Torrent Gas, ATGL, ThinkGas, Gujarat Gas and SGL

Teja Engineering Industries , an engineering services company catering to the energy infrastructure sector, has bagged 18 crore worth of orders from Oil and Natural Gas Corporation.

The company has secured a three-year O&M contract through the Government e-Marketplace for LP Gas Compression facilities at Mandapeta and Tatipaka Installations, Rajahmundry Asset in Andhra Pradesh. The contract valued at 15 crore will be executed in three years.

The company has also received a Letter of Award from ONGC Ankleshwar Asset for providing O&M services at GCP-I, GCP-IV and GCS Motwan. The 6-month contract was valued at 3 crore.

Teja Engineering continues to expand its project footprint across the gas infrastructure ecosystem. The company is currently undertaking projects for leading energy companies including ONGC, GAIL, Adani, AG&P, BPCL, IOAGPL, Torrent Gas, ATGL, ThinkGas, Gujarat Gas and SGL.

Srinivasarao Vakalapudi, Chairman & Managing Director, Teja Engineering Industries, said the new contract reflects the confidence customers placed in the technical capabilities and service quality of the company.

As energy infrastructure continues to expand across the country, the company remains focused on strengthening long-term customer relationships, enhancing operational excellence and creating sustainable value through consistent project execution, he added.

Headline	Over Rs 50cr spent in preparing athletes for CWG		
Publication	The Print	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Over Rs 50cr spent in preparing athletes for CWG

<https://theprint.in/sport/over-rs-50cr-spent-in-preparing-athletes-for-cwg/2991495/>

New Delhi, Jul 20 (PTI) Athletics and boxing received the lion's share of the Sports Ministry's Rs 53.09 crore expenditure to prepare for the scaled

down Glasgow Commonwealth Games and although a medal rush is ruled out due to the event's truncated schedule, improved performances would certainly be expected.

LATEST

Floods, landslides across northern India kill at least 25

Danube water levels reach lowest in 30 years, hampering farm

Chinese rescuers use explosives to clear boulders trapping I

The Odyssey beats The Dark Knight Rises to deliver Christoph

SAD chief Sukhbir Singh Badal appears before SIT in 2015 Beh

NC workers hold protest over statehood issue

Three dead as boulders hits passenger bus, house in J-K

Fire breaks out at Jawahar Bhawan in Lucknow

Karnataka: Cong questions alleged ONGC CSR funds to RSS-link

Kerala Catholic Church reiterates concerns over proposed FCR

Youth Congress leader flags high airfares, limited airline c

CJP says govt has reached out for talks, spokespersons heade

Newly-elected members take oath in Rajya Sabha

Floods, landslides across northern India kill at least 25

Danube water levels reach lowest in 30 years, hampering farm

Chinese rescuers use explosives to clear boulders trapping I

The Odyssey beats The Dark Knight Rises to deliver Christoph

SAD chief Sukhbir Singh Badal appears before SIT in 2015 Beh

NC workers hold protest over statehood issue

Three dead as boulders hits passenger bus, house in J-K

Fire breaks out at Jawahar Bhawan in Lucknow

Karnataka: Cong questions alleged ONGC CSR funds to RSS-link

Kerala Catholic Church reiterates concerns over proposed FCR

Youth Congress leader flags high airfares, limited airline c

CJP says govt has reached out for talks, spokespersons heade

Newly-elected members take oath in Rajya Sabha

The quadrennial showpiece event will feature only 10 able-bodied and six para sports in a heavily pruned schedule to save cost.

The 32-strong athletics contingent, which will be headlined by star javelin thrower Neeraj Chopra among others, will be participating in 21 events in the Games beginning July 23. More than Rs 20 crore has gone into their preparations, which includes training in foreign facilities.

Training-cum-competition in Colorado Springs High Altitude Training Centre in USA along with stints in Switzerland, Turkey, and South Africa were a part of the pre-CWG training.

Sports Minister Mansukh Mandaviya will be heading to Glasgow later tonight and will be interacting with the participating athletes and officials during his stay there. India would also be taking over from Glasgow as the next host of the Games in 2030 during the closing ceremony. The India edition, to be held in Ahmedabad, will go back to being a full-scale Games with 17 disciplines on the roster.

The Glasgow Games do not feature most of the high-yielding sports for India, including badminton, shooting, wrestling, cricket and hockey.

We will do better than last time in disciplines that are there on the roster, said Target Olympic Podium Scheme (TOPS) CEO N S Johal, who also heads the government's Mission Olympic Cell.

On the boxing contingent of 14, seven men and as many women, the government has spent more Rs 10 crore to fund their training and other requirements.

The boxing squad features, among others, Olympic bronze-winner Lovlina Borgohain and is expected to be among the top performers for India.

Rs 7.5 crore has gone into the preparations of 12 weightlifters, including Olympic silver-winning Mirabai Chanu. They have been based in Birmingham for better acclimatisation.

We have ensured that all our medal prospects are based in Europe before the Games so that there is no problem in adapting to local conditions and time zones at the time of the Games, Mandaviya said. PTI PM PM PDS

This report is auto-generated from PTI news service. ThePrint holds no responsibility for its content.

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Headline	महाराष्ट्र के विकास को नई उड़ान देगा ONGC, सीएमडी अरुण कुमार सिंह और मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल की ये मुलाकात		
Publication	amarsandesh	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

महाराष्ट्र के विकास को नई उड़ान देगा ONGC, सीएमडी अरुण कुमार सिंह और मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल की ये मुलाकात

<https://amarsandesh.com/this-meeting-of-ongc-cmd-arun-kumar-singh-and-chief-secretary-rajesh-aggarwal-will-give-a-new-flight-to-the-development-of-maharashtra/>

महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल (आईएस) ने सोमवार को भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन महारत्न सार्वजनिक उपक्रम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिंह से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

इस मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र सरकार और ONGC के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने, आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तथा विकास परियोजनाओं में रणनीतिक निवेश बढ़ाने और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति देने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने ऐसे दीर्घकालिक सहयोग पर जोर दिया, जिससे निवेश, रोजगार सृजन और सतत विकास को बढ़ावा मिल सके।

बैठक में यह भी दोहराया गया कि ONGC महाराष्ट्र के विकास में जिम्मेदार निवेश, मजबूत आधारभूत ढांचे के निर्माण और दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से सार्थक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि ONGC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिंह ऊर्जा क्षेत्र में अपने दूरदर्शी नेतृत्व, प्रभावी निर्णय क्षमता और विकासोन्मुख कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में ONGC ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ राज्यों के समग्र विकास, निवेश और राष्ट्रीय अवसंरचना निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

यह मुलाकात महाराष्ट्र सरकार और ONGC के बीच भविष्य की विकास परियोजनाओं को गति देने तथा राज्य की आर्थिक क्षमता को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।।

Headline	Is India planning to raise ethanol blending beyond E20? Government clarifies		
Publication	Deccan Herald	Edition	Online Coverage
Published Date	21 Jul 2026		

Is India planning to raise ethanol blending beyond E20? Government clarifies

<https://www.deccanherald.com/india/is-india-planning-to-raise-ethanol-blending-beyond-e20-government-clarifies-4081267>

Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi has rejected the claim that E20 is a new or suddenly introduced fuel blend.

The Union government has said that it has not taken any decision to increase the mandated ethanol blending in petrol beyond 20% (E20). It has said that any move towards higher blends will be preceded by detailed scientific studies and consultations with stakeholders.

In his reply to a question in the Rajya Sabha, Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi on Monday said, So far, no decision has been taken by the government for increasing ethanol blending with petrol beyond 20%.

Gopi added that any future decision regarding higher ethanol blends will be taken only after detailed scientific and technical studies and consultations with all relevant stakeholders, including automobile manufacturers, oil marketing companies (OMCs) and research institutions.

Further, Gopi also rejected the claim that E20 is a new or suddenly introduced fuel.

Ethanol has been used as a transport fuel globally for over a century, and India's Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme commenced with a pilot in 2001, he said.

Rather than a sudden shift, the transition to E20 has been phased, calibrated and evidence-based, with blending increasing progressively from 1.53% in 2013-14 to 20% in 2025-26 after scientific evaluation and stakeholder consultations at every stage, he added.

The clarification came after the Petroleum Ministry's June 5 notification of a phased expansion to 85% ethanol-blended petrol (E85). It had prompted concerns and questions if the government was planning to reconsider plans to promote higher ethanol blends.

However, a government official told PTI that the parliamentary reply referred to the national ethanol blending programme for conventional petrol, while the E85 initiative is a separate programme intended for flex-fuel vehicles (FFVs).

The initiative is aimed at adoption of FFVs capable of operating on ethanol blends ranging from E20 to E100, without restricting consumers to a single blend, the official told PTI.

The answer in Parliament is in the context of base blending of ethanol whereas E85 is to cater to the specific flex fuel vehicles, PTI reported, quoting the official.

According to the Petroleum Ministry's statement, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri launched E85 fuel at an Indian Oil Corporation retail outlet in New Delhi on World Environment Day.

The Ministry had said E85 would initially be made available at 48 retail outlets operated by public sector oil marketing companies, before being expanded to 500 outlets by December 2026 and about 5,000 outlets by December 2027.

The rollout commences across 48 public sector OMC retail outlets in the country, enabling flex-fuel vehicle users to access this cleaner fuel. The initiative is slated for nationwide expansion. The same will be scaled up to 500 ROs by December 2026 and about 5,000 ROs by December 2027 and help raise India's aggregate ethanol blending levels to nearly 26% by 2030-31, the Ministry had said.

Headline	Oil ministry working out plan to offset ₹75k cr OMC loss		
Publication	ET Energyworld	Edition	Online Coverage
Published Date	22 Jul 2026		

Oil ministry working out plan to offset ₹75k cr OMC loss

<https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/oil-ministry-working-out-plan-to-offset-75k-cr-omc-loss/132550014>

Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp and Hindustan Petroleum Corp have largely sold petrol, diesel and LPG below market rates since February 28, when the US-Iran war broke out.

The oil ministry is working on a proposal to compensate state-run oil marketing companies (OMCs) after they sought relief for losses of about 75,000 crore incurred in the April-June quarter from selling fuel below market rates, according to people familiar with the matter.

Indian Oil Corp Bharat Petroleum Corp and Hindustan Petroleum Corp have largely sold petrol, diesel and LPG below market rates since February 28, when the US-Iran war broke out. After a truce pulled benchmark Brent crude down to about \$71 a barrel, the companies had hoped to recover their losses before considering any cut in pump prices.

Advt Those hopes have faded as crude has climbed back above \$90 a barrel amid renewed West Asia conflict. The companies have told the government that the losses are too large to absorb without urgent financial support, people aware of the discussions said.

The proposal will require the finance ministry 's approval before being placed before the cabinet and is likely to involve weeks or even months of inter-ministerial negotiations, the people said. For the government, which is already foregoing about 10 per litre in uncollected taxes on petrol and diesel, agreeing to a large compensation package could prove difficult.

Show More Earlier this month, oil minister Hardeep Singh Puri said the three OMCs had incurred losses of 74,781 crore during the April-June quarter. The final figure will become clearer as the companies begin reporting quarterly earnings this week.

The government has historically treated losses on LPG differently from those on petrol and diesel.

While LPG remains a regulated fuel, petrol and diesel are officially deregulated, even though state-run OMCs have largely aligned pump prices with government expectations.

The Centre provided 22,000 crore in 2022 and 30,000 crore last year to compensate OMCs for selling LPG below cost.

Advt However, it has been reluctant to compensate losses on petrol and diesel in recent years because doing so would undermine the principle of deregulation and could trigger similar claims from private fuel retailers.

In the February 2023 budget, the government instead proposed a 30,000 crore equity infusion into the OMCs after they sought compensation for petrol and diesel losses.

Headline	Rs 75,000 cr OMC loss: Oil ministry working on plan to offset losses. Companies seek financial support; Finance Ministry nod needed before proposal goes to Cabinet		
Publication	The Economic Times	Edition	Online Coverage
Published Date	22 Jul 2026		

Rs 75,000 cr OMC loss: Oil ministry working on plan to offset losses. Companies seek financial support; Finance Ministry nod needed before proposal goes to Cabinet

<https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/rs-75000-cr-omc-loss-oil-ministry-working-on-plan-to-offset-losses-companies-seek-financial-support-finance-ministry-nod-needed-before-proposal-goes-to-cabinet/articleshow/132545327.cms>

The Oil Ministry is working on a proposal to compensate state-run oil marketing companies for losses incurred from selling fuel below market rates during the April-June quarter. Hopes of recovering these losses have diminished as crude oil prices have risen again. The government now faces a difficult decision on compensation amid uncollected taxes. Inter-ministerial discussions are expected to take several weeks or even months before a final decision is reached.

The is working on a proposal to compensate state-run oil marketing companies (OMCs) after they sought relief for losses of about 75,000 crore incurred in the April-June quarter from selling fuel below market rates, according to people familiar with the matter.

Corp and Corp have largely sold petrol, diesel and LPG below market rates since February 28, when the US-Iran war broke out. After a truce pulled benchmark Brent crude down to about \$71 a barrel, the companies had hoped to recover their losses before considering any cut in pump prices.

Those hopes have faded as crude has climbed back above \$90 a barrel amid renewed West Asia conflict. The companies have told the government that the losses are too large to absorb without urgent financial support, people aware of the discussions said.

The proposal will require the 's approval before being placed before the cabinet and is likely to involve weeks or even months of inter-ministerial negotiations, the people said. For the government, which is already foregoing about 10 per litre in uncollected taxes on petrol and diesel, agreeing to a large compensation package could prove difficult.

Deregulation Principle Earlier this month, oil minister Hardeep Singh Puri said the three OMCs had incurred losses of 74,781 crore during the April-June quarter. The final figure will become clearer as the companies begin reporting quarterly earnings this week.

The government has historically treated losses on LPG differently from those on petrol and diesel.

While LPG remains a regulated fuel, petrol and diesel are officially deregulated, even though state-run OMCs have largely aligned pump prices with government expectations.

The Centre provided 22,000 crore in 2022 and 30,000 crore last year to compensate OMCs for selling LPG below cost.

However, it has been reluctant to compensate losses on petrol and diesel in recent years because doing so would undermine the principle of deregulation and could trigger similar claims from private fuel retailers.

In the February 2023 budget, the government instead proposed a 30,000 crore equity infusion into the OMCs after they sought compensation for petrol and diesel losses.